वर्ष 12 • अंक 310 • 18 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

शनिवार 15 फरवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 6

वैश्विक खाद्य तेल व्यापार में हलचल

निर्मला सीतारमण पृष्ठ 4

सरकार बजट में बदलाव को तैयार

डॉलर रु. 71.40 ▲ 10 पैसे | यूरो रु. 77.40 ▼ 10 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 40617 ▲ 14 रुपये | सेंसेक्स 41257.70 ▼ 202.10 | निफ्टी 12113.50 ▼ 61.20 | निफ्टी फ्यूचर्स 12129.70 ▲ 16.20 | ब्रेंट क्रूड 57.00 डॉलर ▲ 0.60 डॉलर

एक नज़र

थोक महंगाई जनवरी में बढ़कर 3.1 प्रतिशत हुई

थोक कीमतों पर आधारित महंगाई दर जनवरी में बढ़कर 3.1 प्रतिशत हो गई। दिसंबर में यह दर 2.59 प्रतिशत रही थी। प्याज और आलू जैसी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते यह इजाफा हुआ है। थोक महंगाई एक साल पहले समान अवधि में 2.76 प्रतिशत थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार इस दौरान गैर-खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी दिसंबर के 2.32 प्रतिशत से लगभग तीन गुना बढ़कर 7.8 प्रतिशत हो गई।

एवेन्यू सुपरमार्ट्स ओएफएस को 3.4 गुना अभिदान

एवेन्यू सुपरमार्ट्स की शेयर बिक्री की पेशकश को शुक्रवार को 3 गुना से अधिक अभिदान मिला। कंपनी के ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के तहत 4.53 करोड़ शेयरों के लिए संस्थागत निवेशकों की तरफ से बोलियां आईं। ओएफएस में 1.33 करोड़ शेयरों की पेशकश की गई है। ज्यादातर बोलियां 2,258 रुपये के स्तर पर आईं, जो आधार मूल्य 2,049 रुपये से 10 प्रतिशत अधिक है। शेयर बाजार में शुक्रवार को कंपनी का शेयर 5.6 प्रतिशत कमजोर होकर 2,401 पर बंद हुआ।

निर्यात में लगातार छठे महीने आई गिरावट

इंजीनियरिंग वस्तुएं, आभूषण एवं परिधान उद्योग के कमजोर प्रदर्शन के कारण देश से होने वाला निर्यात जनवरी में 1.60 प्रतिशत कम होकर 25.9 अरब डॉलर रह गया। दिसंबर में निर्यात 1.8 प्रतिशत कम रहा था। शुक्रवार को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार लगातार छठे महीने निर्यात में कमी दर्ज हुई है। चालू वित्त वर्ष के पहले दस महीने में देश का कुल संचयी निर्यात 265.3 अरब डॉलर रहा। आलोच्य महीने में आयात में भी कमी देखी गई और यह 0.75 प्रतिशत कम होकर 41.14 अरब डॉलर रहा। इस तरह, जनवरी में व्यापार घाटा 15.17 अरब डॉलर दर्ज किया गया। पृष्ठ 4

बीएस-4 वाहनों की बिक्री की समय सीमा नहीं बढ़ेगी

उच्चतम न्यायालय ने भारत स्टेज (बीएस-4) वाहनों की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है। शुक्रवार को इस संबंध में न्यायालय ने वाहन डीलरों की याचिका खारिज कर दी। वाहन डीलरों ने अपनी याचिका में बीएस-4 वाहनों की बिक्री की समय सीमा 1 अप्रैल, 2020 से एक महीना बढ़ाए जाने की मांग की थी। इससे पहले शीर्ष न्यायालय ने 24 अक्टूबर, 2018 को अपने आदेश में कहा था कि 1 अप्रैल, 2020 के बाद बीएस-4 वाहनों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आज का सवाल

क्या दूरसंचार क्षेत्र के दबाव से बैंक भी होंगे प्रभावित

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या बढ़ते घाटे से और बढ़ेगी वोडाफोन आइडिया की मुश्किल?	हां	90.91%
	नहीं	09.09%

एजीआर पर कोर्ट की फटकार

शीर्ष अदालत ने दूरसंचार कंपनियों की याचिका खारिज की, दूरसंचार विभाग की भी खिंचाई

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 14 फरवरी

- अदालत ने आदेश के अनुपालन में तत्काल कार्रवाई करने को कहा
- कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को अगली सुनवाई पर पेश होने के निर्देश
- दूरसंचार विभाग ने कंपनियों को शुक्रवार रात तक बकाया चुकाने को कहा

उच्चतम न्यायालय ने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाये के किस्तों में भुगतान की मांग वाली भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की संशोधित याचिकाओं को आज खारिज कर दिया। न्यायालय ने इस कंपनियों को उसके 24 अक्टूबर के आदेश के मुताबिक बकाये का भुगतान करने को कहा है। अदालत से कंपनियों को राहत नहीं मिलने के बाद भारती को 35 हजार करोड़ रुपये और वोडा आइडिया को 54 हजार करोड़ रुपये तत्काल चुकाने होंगे। कंपनियों पर कुल एजीआर बकाया 1.47 लाख करोड़ रुपये है। उच्चतम न्यायालय ने साथ ही गैर दूरसंचार कंपनियों की याचिका को भी खारिज कर दिया और उन्हें अलग से याचिका दायर करने को कहा।

न्यायालय ने दूरसंचार विभाग और भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि इन कंपनियों ने उसके आदेश का उल्लंघन किया है और यह अच्छी स्थिति नहीं है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि जिस तरह से चीजें हो रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि वे अदालत के आदेशों का सम्मान नहीं करते हैं।

न्यायालय से मिली फटकार के बाद दूरसंचार विभाग ने तुरंत हरकत में आते हुए अपने उस पत्र को वापस ले लिया जिसमें कहा गया था कि एजीआर बकाये के भुगतान में देरी पर कंपनियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक कंपनियों को 23 जनवरी तक बकाये का भुगतान करना था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूरसंचार विभाग ने एक अलग पत्र में कहा है कि एजीआर भुगतान योजना के तहत कंपनियों को लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क से संबंधित सभी बकायों का भुगतान करना है। न्यायालय के आदेश के तुरंत बाद सरकार ने कंपनियों को तत्काल भुगतान करने को कहा। भारती एयरटेल ने 10 हजार करोड़ रुपये के भुगतान पर सहमति जताई है। विभाग को भेजे एक पत्र में एयरटेल ने कहा है कि वह 20 फरवरी तक यह राशि जमा करा देगी। बाकी राशि वह 17 मार्च को अगली सुनवाई से पहले चुका देगी।

कंपनी 22 सर्किलों में अपना आकलन कर रही है और केंद्र सरकार को भरोसा दिया है कि वह शेष रकम का भुगतान जल्द ही कर देगी। उच्चतम न्यायालय के आदेश में कहा गया है, 'यह स्पष्ट है कि अदालत द्वारा आदेश देने के बाद भी उसका अनुपालन नहीं किया गया। ऐसे में उक्त व्यक्तियों को अगली सुनवाई (17 मार्च, 2020) के दिन व्यक्तिगत तौर पर अदालत में पेश होना होगा।' भुगतान रणनीति को लेकर वोडाफोन आइडिया ने कोई जानकारी नहीं दी है।

बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, 'समीक्षा याचिका और संशोधन याचिका वोडाफोन आइडिया के पक्ष में नहीं रही। ऐसे में मेरे विचार से भारत का दूरसंचार बाजार दो कंपनियों तक सिमट सकता है। लेकिन यह आदर्श स्थिति नहीं होगी क्योंकि भारती एयरटेल और रिलायंस जियो का नेटवर्क 30 करोड़ अतिरिक्त ग्राहकों के भार को वहन करने में सक्षम नहीं हो सकती है।'

■ संबंधित खबर : पृष्ठ 2

घबराएं नहीं वोडा-आइडिया के ग्राहक : विशेषज्ञ

वोडाफोन आइडिया अगर दिवालिया आवेदन करती है तो उसके ग्राहकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट (एनसीएलटी) में जाने के बाद भी कंपनी अपनी सेवाओं का परिचालन जारी रख सकती है। इसका सीधा मतलब है कि वोडाफोन के करीब 30 करोड़ ग्राहकों की सेवाएं तत्काल बंद नहीं होगी और न ही उन्हें तुरंत किसी अन्य कंपनी में अपना नंबर पोर्ट करना होगा। पृष्ठ 2

सरकारी बैंकों के विलय पर संशय

सोमेश झा और हंसिनी कार्तिक
नई दिल्ली/मुंबई, 14 फरवरी

- दस सरकारी बैंक के विलय की है योजना
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी योजना को नहीं दी है मंजूरी
- बैंक ऑफ बड़ौदा के विलय के नतीजे देखना चाहते हैं मोदी
- 1 अप्रैल की समयसीमा में अब कुछ ही दिन बाकी

दस सरकारी बैंकों को मिलाकर चार बैंक बनाने की घोषणा के छह महीने बाद सरकार इस मामले में फूंक-फूंककर कदम आगे बढ़ा रही है जबकि बैंकों के बहीखाते के विलय की समयसीमा केवल डेढ़ महीने दूर है।

एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बैंकों के विलय पर अंतिम फैसला लेने से पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में दो अन्य बैंकों के विलय का परिणाम देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, 'वह बैंक ऑफ बड़ौदा के विलय की समीक्षा करना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि इससे क्या फायदा हुआ है। बैंकों के विलय पर अभी यही स्थिति है।'

सरकारी बैंकों के विलय की योजना से जुडी अधिसूचना में देरी के कारण यह आशंका पैदा हुई है कि विलय प्रक्रिया में देर हो सकती है। यह प्रक्रिया अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल, 2020 से शुरू होनी है। बैंकों के विलय के बारे में अंतिम फैसला लेने से पहले वित्त मंत्रालय जल्दी ही इस बारे में प्रधानमंत्री को एक प्रस्तुति दे सकता है।

बैंक ऑफ बड़ौदा के ताजा वित्तीय नतीजे सरकार के लिए चिंता का विषय हैं। ऊंचे प्रावधान के कारण बैंक को इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 1,407 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ है। बैंक का फंसा कर्ज 10,387 करोड़ रुपये बढ़ गया। (शेष पृष्ठ 4 पर)

एमेजॉन व फ्लिपकार्ट के खिलाफ जांच के आदेश पर अंतरिम रोक

एजेंसियां
बेंगलूरु, 14 फरवरी

- सीसीआई ने दिए थे एमेजॉन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ जांच के आदेश
- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कंपनियों को दी फौरी राहत

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों एमेजॉन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) के जांच के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। सीसीआई ने प्रतिस्पर्द्धा नियमों के कथित उल्लंघन के आरोप में इन दोनों कंपनियों के खिलाफ जांच का आदेश दिया था। इस मामले से जुड़े एक वकील ने कहा कि न्यायालय ने सीसीआई द्वारा दिए जांच के आदेश पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने दोनों पक्षों को आठ हफ्ते का समय दिया है।

एमेजॉन ने सोमवार को न्यायालय में सीसीआई के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में एमेजॉन ने 13 जरवरी 2020 को सीसीआई द्वारा दिए जांच का आदेश निरस्त करने की मांग की थी। जनवरी में बाजार में कारोबारी प्रतिस्पर्द्धा पर नजर रखने वाले सीसीआई ने कथित अनुचित व्यवहार और कुछ खास विक्रेताओं के साथ सांठगांठ के आरोप में फ्लिपकार्ट और एमेजॉन के खिलाफ जांच का आदेश दिया था। स्मार्टफोन एवं संबंधित उपकरणों के कारोबारियों के संगठन दिल्ली व्यापार महासंघ ने इन दोनों कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी याचिका में एमेजॉन ने कहा कि सीसीआई ने तथ्यों पर पूरी तरह विचार किए बिना आदेश दिया है और जांच की स्थिति में कंपनी की साख पर बुरा असर होगा। इस बीच, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कहा है कि वह उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील करेगा। इस बीच, कैट प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच को गति देने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालेगा। कैट ने एक बयान में कहा कि उसका एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलेगा।

एक क्लिक पर निपटेंगे बीमा दावे!

नम्रता आचार्य
कोलकाता, 14 फरवरी

1.59 करोड़ के दावों के निपटान में किया गया
34,983 करोड़ रुपये का भुगतान

प्रति दावा **21,984** रुपये किया गया औसत भुगतान

72 फीसदी दावों का निपटान टीपीए के जरिये किया गया

54 फीसदी दावों का निपटान कैशलेस सुविधा के तहत हुआ

कुल दर्ज दावों में निपटान का प्रतिशत **72** फीसदी रहा, **8** फीसदी दावे हैं लंबित

स्रोतः आईआरडीए

स्वास्थ्य बीमा के दावों का निपटान जल्द ही एक क्लिक पर उपलब्ध होगा। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) इस प्रक्रिया के लिए साझा पोर्टल बनाने का प्रस्ताव कर रहा है।

उद्योग संगठन एसोचैम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में आईआरडीएआई की सदस्य (गैर-जीवन बीमा) टीएल अलामेलू ने कहा कि नियामक चाहता है कि स्वास्थ्य बीमा से जुड़े सभी हितधारकों- बीमाकर्ता, बीमित व्यक्ति के साथ ही साथ अस्पतालों को एक साथ लाया जाए और एक मानकीकृत और समयबद्ध दावा निपटान प्रक्रिया बनाई जाए। बीमा नियामक ने इस मामले पर विचार करने के लिए एक समिति का भी गठन किया है और इस मंच को इंश्योरेंस इन्फॉर्मेटिक्स ब्यूरो द्वारा विकसित किया जाएगा।

अलामेलू ने कहा, 'इससे स्वास्थ्य बीमा के दावों के निपटान के तरीके में अमूलचूल बदलाव आने की उम्मीद है।' वर्तमान व्यवस्था में दावों का निपटारा थर्ड पार्टी प्रशासक (टीपीए) या इन-हाउस दावा निपटान टीम के माध्यम से किया जाता है। इसमें आम तौर पर दावे का निपटान करने में करीब एक महीने का वक्त लग जाता है। दोनों ही प्रक्रिया के अपने गुण-दोष हैं। उदाहरण के लिए नकद रहित (कैशलेस) निपटान में टीपीए का अस्पतालों के साथ गठजोड़ रहता है, जिससे निपटान की प्रक्रिया सुगम होती है। इन-हाउस निपटान में दावे के निपटान में कम समय लगता है क्योंकि इसमें बीमाकर्ता और बीमित व्यक्ति के बीच सीधे बातचीत होती है।

अलामेलू ने कहा कि साझा पोर्टल के जरिये नकद रहित और प्रतिपूर्ति दोनों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'इस तरह के मंच को गठित करने का मकसद सभी हितधारकों- बीमाकर्ता, बीमित व्यक्ति और अस्पतालों को एकसाथ लाना है। सभी तरह के दावों का निपटान इसी के तहत निर्धारित समय के अंदर किया जाएगा।' आईआरडीएआई पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य बीमा को मानकीकरण करने की दिशा में काम कर रहा है। इसके साथ ही नियामक ग्राहकों को अपनी पसंद का टीपीए चुनने की भी सुविधा देने की योजना बना रहा है।

बुरे हालात के लिए तैयार बैंक

अनूप रॉय और देवाशिष महापात्र
मुंबई/बेंगलूरु 14 फरवरी

वोडाफोन-आइडिया को बैंकों का कर्ज

बैंक	रकम (करोड़ रुपये)
एसबीआई	11,200
आईडीबीआई बैंक	10,900
येस बैंक	4,000
इंडसइंड बैंक	3,000
आईडीएफसी बैंक	3,200
आईसीआईसीआई बैंक	1,700
ऐक्सिस बैंक	1,000
पीएनबी	1,000
एचडीएफसी बैंक	500

स्रोत : एमसीए, विश्लेषक, कंपनी

एक तरफ उच्चतम न्यायालय दूरसंचार क्षेत्र की बकाया रकम को लेकर कड़े रुख अख्तियार कर रहा है वहीं दूसरी तरफ बैंक अपने फंसे हुए कर्ज में और बढ़ोतरी के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। नैस्कॉम सम्मेलन से इतर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के अध्यक्ष रजनीश कुमार कहते हैं, 'अब यह दूरसंचार कंपनियों को तय करना है कि किस तरह के कदम उठाए जाएंगे।' दूरसंचार क्षेत्र में फंडिंग के जरिये बैंकों की करीब 29,000 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है। वहीं गैर-फंडिंग के जरिये भी बैंकों ने इस क्षेत्र में 14,000 से 15,000 करोड़ रुपये लगाए हैं।

कुमार के मुताबिक दूरसंचार क्षेत्र में एसबीआई का 9,000 करोड़ रुपये बतौर कर्ज फंसा था और बैंक कुछ रिकवरी की उम्मीद कर रही है। लेकिन बैंकों ने मानक परिसंपत्ति पर कोई प्रावधान नहीं रखा था। हालांकि बैंक को अब कोई भ्रम नहीं है। कुमार ने कहा, 'हम बुरी स्थिति के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं।' एसबीआई के चेयरमैन कई तरह से पूरे बैंकिंग तंत्र की धारणा का संकेत दे रहे थे। बैंकरों और विश्लेषकों का कहना है कि इस क्षेत्र को दिया गया ऋण भले ही तात्कालिक रूप से फंसे कर्ज में न तब्दील हो लेकिन इसके बड़े हिस्से की रिकवरी नहीं हो सकती है। बैंकों द्वारा किए गए शीर्ष 10 निवेश का जायजा लेने पर यह अंदाजा मिलता है कि बैंक पर दूरसंचार कंपनियों की उधारी 1.8 लाख करोड़ रुपये है जिनमें से फंड आधारित निवेश ही करीब 1.24 लाख करोड़ रुपये है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक कंपनियों को 17 मार्च तक समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाये का भुगतान दूरसंचार विभाग को करना है और यह रकम करीब 1.47 लाख करोड़ रुपये तक की है। यह बकाया रकम उन कंपनियों का भी है जो दिवालिया हो चुकी हैं। हालांकि इनमें फंसे कर्ज की रकम कितनी है यह स्पष्ट नहीं है क्योंकि बैंक इसका खुलासा नहीं करते हैं।

वोडाफोन आइडिया को 50,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना है जबकि भारती एयरटेल को 35,500 करोड़ रुपये और टाटा टेलीसर्विसेज पर 14,000 करोड़ रुपये की रकम बकाया है जबकि इसने अपना मोबाइल कारोबार एयरटेल को बेच दिया है। वोडाफोन आइडिया के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला ने पहले ही कहा है कि एजीआर बकाया पर सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिली है ऐसे में कंपनी को अपना कारोबार बंद करना पड़ेगा। बिड़ला ने दिसंबर में ही कहा था, 'अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा तब मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया के लिए यह कहानी का अंत ही है। फंसी हुई रकम के बाद ऊपर से रकम लगाने का कोई मतलब नहीं है। हम कारोबार बंद कर देंगे।' अगर वोडाफोन कारोबार बंद करती है तो यह बैंकिंग उद्योग के लिए बड़ा झटका होगा। बैंकरों का कहना है कि वे वित्तीय संसाधन में कमी की प्रक्रिया के तहत पुराने 3जी और 5जी स्पेक्ट्रम की बिक्री मौजूदा खिलाड़ियों को करने पर ही रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं। नए 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी जल्द ही होनी है। प्रावधान के जरिये बैंकों पर तत्काल असर होगा। मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज में बैंकिंग विश्लेषक नितिन अग्रवाल कहते हैं, 'इससे पहले की तिमाही में डीएचएफएल को गैर-निष्पादित खाते में डालने के बाद बैंकिंग क्षेत्र को अन्य बड़ी कंपनियों के खाते से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।' अग्रवाल ने कहा, 'उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को बैंकिंग तंत्र की परिसंपत्ति गुणवत्ता पर चिंता जताई है क्योंकि कई बैंकों का दूरसंचार क्षेत्र में फंड तथा गैर-फंड निवेश है खासतौर पर वोडाफोन आइडिया जो काफी घाटे में है।

एसबीआई, आईडीबीआई बैंक, यस बैंक, इंडसइंड बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपेक्षाकृत ज्यादा निवेश किया है जबकि पिछली तिमाही के दौरान केवल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 50 फीसदी प्रावधान किया है।'

दूरसंचार क्षेत्र में संकट बढ़ने की वजह से ही इस हफ्ते से पहले मूडीज ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग स्थिर के बजाय नकारात्मक कर दी है। विश्लेषक और बैंकर इस मुद्दे पर और स्पष्टता बनने के लिए 16 मार्च तक का इंतजार करेंगे जिस दिन अगली सुनवाई होनी है।

दिसंबर 2019 तक दूरसंचार क्षेत्र में आईडीबीआई बैंक का निवेश 5,554 करोड़ रुपये है जिनमें से 5,349 करोड़ रुपये गैर-फंडेड जबकि बाकी 205 करोड़ रुपये फंडिंग वाला निवेश है। जबकि कुल फंसा कर्ज करीब 28 करोड़ रुपये है।

वरिष्ठ आईडीबीआई बैंक के अधिकारी का कहना है कि बैंक ने गारंटी के रूप में गैर-फंडिंग वाला निवेश किया है जो ज्यादातर वोडाफोन में किया गया है। अगर लाभार्थी गारंटी को खत्म करता है तब यह फंडिंग वाला निवेश हो जाएगा। हालांकि फंडेड निवेश होने के बावजूद कर्ज लेने वालों को भुगतान के लिए केवल तीन महीने का वक्त मिलेगा। इसका भुगतान न करने की स्थिति में यह गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (फंसे कर्ज) की श्रेणी में चला जाएगा और पहले साल में इसका प्रावधान 15 फीसदी होगा। ऐसे में अधिकारियों का कहना है कि इसका तत्काल असर नहीं पड़ेगा।

वोडा आइडिया का रास्ता बंद!

दिसंबर तिमाही के बाद उसकी हैसियत रिकॉर्ड निचले स्तर 17,600 करोड़ रुपये रह गई है जबकि कर्ज-इक्विटी अनुपात बढ़कर 5.7 गुना पर पहुंच गया है जो उसे देश में ज्यादा कर्जदार कंपनियों में से एक बनाता है

देव चटर्जी और कृष्ण कांत
मुंबई, 14 फरवरी

शुक्रवार को वोडाफोन आइडिया के मुंबई स्थित मुख्यालय में निराशाजनक माहौल नजर आया, जहां कंपनी के आला अधिकारी यह कहते नजर आए कि कंपनी 27,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय झटका नहीं सह पाएगी और कंपनी को आखिरकार दिवालिया अदालत का रुख करना पड़ेगा।

वोडाफोन के एक अधिकारी ने कहा, इस फैसले के बाद कंपनी के लिए वित्तीय रूप से अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाएगा।

वोडाफोन की हैसियत दिसंबर 2019 की तिमाही में सालाना आधार पर 73 फीसदी घटकर 17,600 करोड़ रुपये रह गई जब कंपनी ने तिमाही के दौरान करीब 6,400 करोड़ रुपये का शुद्ध नुकसान दर्ज किया। संचयी तौर पर पिछली चार तिमाहियों में कंपनी की हैसियत में करीब 45,000 करोड़ रुपये की कमी आई है, जो तीन साल का निचला स्तर है।

विश्लेषकों का कहना है कि इतनी कम हैसियत और परिचालन में जारी नुकसान को देखते हुए कंपनी को एजीआर का बकाया चुकाने के लिए लेनदारों से नया कर्ज मिलने की संभावना खत्म हो गई है। एक विश्लेषक ने कहा, 'आखिर बैंक किस आधार पर इस कंपनी को नया कर्ज देंगे? कंपनी के पास इस उधारी को सहारा देने के लिए परिसंपत्तियां ही नहीं हैं।'

तीसरी तिमाही के नतीजे के बाद वोडाफोन आइडिया का लंबी अवधि का कर्ज-इक्विटी अनुपात बढ़कर 5.7 गुना हो गया है, जो उसे देश में सबसे बड़ी कर्जदार कंपनी में से एक बनाता है। इसकी तुलना में उसका कर्ज अनुपात मार्च 2019 की तिमाही में 1.3 गुना था। अगर हम इसमें लंबी अवधि के कर्ज की मौजूदा परिपक्वता को जोड़ लें तो दिसंबर 2019 के आखिर में कंपनी का कर्ज अनुपात बढ़कर 6.6 गुना हो गया। कंपनी को वित्त वर्ष 2020 के आखिर तक लंबी अवधि का 14,800 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाना है। यह जानकारी कंपनी की तीसरी तिमाही की फाइलिंग से मिली।

ऐसे में कई विश्लेषकों को उम्मीद है कि कंपनी अगली कुछ तिमाहियों में अपनी शुद्ध हैसियत के नकारात्मक हो जाने पर दिवालिया प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकती है। वोडाफोन आइडिया के कमजोर वित्तीय प्रदर्शन से पिछले एक साल में उसके बाजार पूंजीकरण में तेज गिरावट आई है, जो उसे भारती एयरटेल की तरह बाजार से नई इक्विटी पूंजी जुटाने में मुश्किल खड़ा कर रहा है।

मौजूदा शेयर भाव पर वोडाफोन आइडिया का बाजार पूंजीकरण करीब 10,000 करोड़ रुपये है, जो साल 2007 में आइडिया सेल्युलर के तौर पर सूचीबद्ध होने के बाद का निचला स्तर है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण मार्च 2007 में सूचीबद्धता के समय करीब 22,000 करोड़ रुपये था। विश्लेषकों ने कहा कि कंपनी को प्रवर्तकों आदित्य बिड़ला समूह व वोडाफोन पीएलसी से बड़ी इक्विटी की दरकार है ताकि उसकी मौजूदगी कायम रहे और वह एजीआर का भुगतान कर सके।

पिछले दशक में जिन बाजारों से बाहर निकला वोडाफोन समूह

देश/बाजार*	साल
मिस्र	2020
न्यूजीलैंड	2019
माल्टा	2019
अमेरिका	2013
फिजी	2014
जापान	2006
फ्रांस	2011
पोलैंड	2011

* स्थानीय ऑपरेटर में हिस्सा समेत, जहां वोडाफोन पीएलसी अल्पांश साझेदार या हिस्सेदार थी
स्रोत : कैपिटालाइन, मीडिया की घोषणाएं

हालांकि प्रवर्तकों ने कंपनी में और रकम नहीं लगाने का फैसला लिया है क्योंकि पिछले साल कंपनी के 25,000 करोड़ रुपये के राइट्स इश्यू में अच्छी खासी रकम निवेश करने के बाद दोनों प्रवर्तक काफी रकम गंवा चुके हैं। वोडाफोन पीएलसी के पास वोडाफोन आइडिया की 44.39 फीसदी हिस्सेदारी है जबकि आदित्य बिड़ला समूह के पास 27.18 फीसदी हिस्सेदारी है।

चूंकि आदित्य बिड़ला समूह ने 1.15 लाख करोड़ रुपये के कर्ज पर कॉरपोरेट गारंटी नहीं दी है, लिहाजा आदित्य बिड़ला समूह की कंपनियों पर इसका नकारात्मक असर नहीं होगा और उनका नुकसान कंपनी की इक्विटी हिस्सेदारी तक सीमित होगा। यह जानकारी एक विश्लेषक ने दी। वोडाफोन आइडिया ने सितंबर 2019 के आखिर तक विवादित एजीआर की देनदारी के मद में कुल 44,150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। 30 सितंबर 2019 तक मौजूदा 15,390 करोड़ रुपये की नकदी 27,610 करोड़ रुपये के लाइसेंस शुल्क की देनदारी के भुगतान के लिए अपर्याप्त होगी।

पिछले साल नवंबर में वोडाफोन पीएलसी के सीईओ निक रीड ने चेतावनी दी थी कि 24 अक्टूबर के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद वोडाफोन आइडिया बंद होने की ओर बढ़ रही है। उस फैसले में दूरसंचार कंपनियों से तीन महीने के भीतर बकाया चुकाने को कहा गया था। इसकी समयसीमा इस साल जनवरी में ही खत्म हो गई।

यह स्थिति वोडाफोन के भारत से निकलने की संभावना में इजाफा करती है, अगर वोडाफोन आइडिया वित्तीय मुश्किलों के कारण अपना परिचालन निलंबित करने को बाध्य हो। विगत में वोडाफोन आइडिया करीब आठ बाजारों से बाहर निकल चुकी है। इन बाजारों से निकलने की मुख्य वजह वाणिज्यिक रही है और कंपनी ने इस निकासी में से ज्यादातर में कमाई की। उदाहरण के लिए वोडाफोन पीएलसी जब अमेरिकी संयुक्त उद्यम वेरिजॉन वायरलेस से निकली तो उसे करीब 130 अरब डॉलर मिले, वहीं मिस्र के संयुक्त उद्यम की हिस्सेदारी करीब 2.4 अरब डॉलर में बेची।

दो फर्मों वाले बाजार की ओर बढ़ रहा दूरसंचार

भारती व जियो को होगा फायदा क्योंकि एजीआर करा सकता है वोडा आइडिया का रास्ता बंद

राम प्रसाद साहू
मुंबई, 14 फरवरी

वोडाफोन आइडिया का शेयर 23 फीसदी से ज्यादा टूट गया जब सर्वोच्च न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों की संशोधित याचिका खारिज कर दी। वोडाफोन आइडिया ने पहले संकेत दिया था कि वह अपना परिचालन जारी रखने की स्थिति में नहीं होगी अगर एजीआर के मामले में विपरीत फैसला आता है। वोडाफोन पर एजीआर का 53,000 करोड़ रुपये बकाया है जबकि भारती एयरटेल पर 35,600 करोड़ रुपये।

ब्रोकरेज कंपनियों का मानना है कि जब तक सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, वोडाफोन को अपनी दुकान बंद करनी पड़ सकती है। एसबीआईकैप रिसर्च के राजीव शर्मा और अंशुल अग्रवाल ने संकेत दिया कि इस घटनाक्रम के बाद दूरसंचार क्षेत्र में और एकीकरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और यह सिर्फ समय की बात है जब भारतीय दूरसंचार क्षेत्र दो कंपनियों वाला बाजार बन जाएगा।

उनके मुताबिक, एजीआर पर फैसले ने वोडाफोन आइडिया के अस्तित्व को लेकर गंभीर चिंता पैदा की है क्योंकि उसकी बैलेंस शीट कमजोर है। उन का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2020 में कर्ज व परिचालन लाभ का अनुपात 27 गुने पर पहुंच जाएगा। कंपनी का परिचालन लाभ दिसंबर तिमाही में उसकी ब्याज लागत से कम रहा। कंपनी का कर्ज 1.033 लाख करोड़ रुपये है जबकि उसकी हैसियत तिमाही के आखिर में 17,623 करोड़ रुपये थी।

चूंकि यह क्षेत्र दो कंपनियों वाले बाजार की ओर बढ़ रहा है, लिहाजा स्पष्ट तौर से इसका फायदा भारती एयरटेल और रिलायंस जियो को होगा। विश्लेषकों का अनुमान है कि टैरिफ में बढ़ोतरी होगी क्योंकि कीमत की ताकत वापस इस क्षेत्र में आ गई है। सभी दूरसंचार कंपनियों ने दिसंबर में टैरिफ बढ़ाए थे और ये चीजें उनके मार्च तिमाही के नतीजे में प्रतिबिंबित होने की संभावना है। अगर यह क्षेत्र दो कंपनियों वाले बाजार में तब्दील होता है तो इससे जियो को 50 फीसदी राजस्व बाजार हिस्सेदारी का लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी। अभी उसकी राजस्व बाजार हिस्सेदारी 34.9 फीसदी है। भारती को भी इसका फायदा मिलेगा, जिसका शेयर 4.6 फीसदी चढ़ गया। कंपनी की लागत हालांकि बढ़ने की संभावना है क्योंकि वह वोडाफोन आइडिया के साथ टावर का बुनियादी ढांचा साझा करती है। भारती इन्फ्राटेल के लिए टीनेंसी अनुपात घटेगा, अगर वोडाफोन आइडिया परिचालन बंद करती है। ऐसे में भारती एयरटेल के लिए टावर का किराया बढ़ सकता है।

वोडाफोन आइडिया के ग्राहक न घबराएं

सुरजीत दास गुप्ता
नई दिल्ली, 14 फरवरी

वोडाफोन आइडिया अगर दिवालिया प्रक्रिया में जाने के लिए अर्जी लगाती है तब भी उसके ग्राहकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह यह है कि ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट (एनसीएलटी) में जाने के बाद भी कंपनी अपनी सेवाओं का परिचालन जारी रख सकती है।

आईबीसी नियमों के अनुसार ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) समाधान पेशेवर की नियुक्ति करते हैं जो खरीदार तलाशने के साथ ही कंपनी के कामकाज को संभालते हैं। इस दौरान कंपनी के निदेशक मंडल के अधिकार निलंबित रहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि वोडाफोन के करीब 30 करोड़ ग्राहकों की सेवाएं तत्काल बंद नहीं होगी और न ही उन्हें तुरंत किसी अन्य कंपनी में अपना नंबर पोर्ट करना होगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा तीनों ऑपरेटरों के पास इतनी बड़ी संख्या में ग्राहकों को सेवाएं देने के लिए नेटवर्क क्षमता नहीं है। ऐसा करने के लिए उन्हें काफी पैसा लगाना होगा और अपनी क्षमता दोगुनी करनी होगी। दूरसंचार कंपनियों का कहना है कि वे करीब 10 करोड़ अतिरिक्त ग्राहकों को ही चरणबद्ध तरीके से अपने नेटवर्क में शामिल कर सकती हैं।

लेकिन अभी तक यह रुख रहा है कि किसी कंपनी के बिक्री के लिए रखे जाने की खबर आते ही ग्राहकों का बड़ा हिस्सा सेवाओं की गुणवत्ता

जानकारों के मुताबिक दूरसंचार कंपनी के दिवालिया प्रक्रिया में जाने की स्थिति में भी उसकी सेवाएं फौरन नहीं होंगी बंद

खराब होने की आशंका के चलते उससे अलग हो जाते हैं। यह उस समय खास तौर पर होता है जब प्रबंधन का जोर बाजार में प्रतिस्पर्द्धा करने के बजाय कंपनी की बिक्री पर लग जाता है।

ऐसी स्थिति में अगर आईबीसी प्रावधानों के तहत परिसंपत्ति बिक्री की प्रक्रिया में देर होती है तो उसके मूल्यांकन में अच्छी-खासी गिरावट आ जाती है। अतीत में एयरसेल के साथ ऐसा हो चुका है। एयरसेल की बिक्री में कर्जदाताओं को 99 फीसदी नुकसान उठाना पड़ा था और ग्राहक दूसरी दूरसंचार कंपनियों की सेवाएं लेने लगे थे।

कर्ज समाधान प्रक्रिया से गुजर चुकी दूरसंचार कंपनियों का कहना है कि केवल कामकाज समेटने की स्थिति में ही उन्हें ग्राहकों को 90 दिन का नोटिस देना होता है और दूसरे नेटवर्क पर नंबर पोर्ट कराने में मदद भी करनी होती है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब दिवालिया कंपनी से गुजर रही कंपनी को कोई खरीदार न मिले। अपना कामकाज बंद कर चुकी रिलायंस कम्युनिकेशंस के मामले में उसके करीब 8.5 करोड़ ग्राहकों ने दूसरे कंपनियों के पास अपने नंबर पोर्ट कराए थे।

सवाल यह उठता है कि क्या वोडाफोन आइडिया को कोई खरीदार मिल पाएगा? विश्लेषकों का कहना है कि प्रतिस्पर्द्धा प्रावधान लागू किए जाने पर रिलायंस जियो या भारती एयरटेल जैसी बड़ी दूरसंचार कंपनियों के लिए इसे खरीद पाना असंभव हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि प्रतिस्पर्द्धा कानून के मुताबिक किसी भी एक कंपनी के पास 50 फीसदी से अधिक बाजार हिस्सेदारी नहीं हो सकती है। और वोडा आइडिया जैसी बड़ी कंपनी को खरीदने पर जिया या एयरटेल दोनों ही इस सीमा को पार कर जाएंगे।

ऐसी स्थिति में एक नई कंपनी का इस खरीद में जुड़ने की संभावना बन सकती है। विश्लेषकों के मुताबिक नई दूरसंचार कंपनी को कई तरह की छूट सुविधाएं मिलेंगी। पहली बात यह है कि उस कंपनी को वोडा आइडिया के दिवालिया प्रक्रिया में चले जाने पर उस पर बकाया 50,000 करोड़ रुपये का समायोजित राजस्व (एजीआर) नहीं देना होगा। वैसे दूरसंचार विभाग एक असुरक्षित कर्जदाता के तौर पर इस राशि की मांग कर सकता है। आरकॉम के मामले में भी यही तरीका अपनाया गया था। दूसरी बात यह है कि सरकारी नियमों के मुताबिक संभावित खरीदार को दो साल तक विलंबित स्पेक्ट्रम शुल्क नहीं देना होगा।

टाटा टेलीसर्विसेज का एजीआर बकाया चुकाएगी टाटा संस

टाटा टेलीसर्विसेज पर 14,000 करोड़ रुपये बकाया है जबकि दिसंबर 2019 के आंकड़ों के मुताबिक उसके पास सिर्फ 200 रुपये की नकदी है

देव चटर्जी
मुंबई, 14 फरवरी

टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस पहले ही टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड का 14,000 करोड़ रुपये का एजीआर बकाया चुकाने के लिए बैंकों से रकम का इंतजाम कर चुकी है। साथ ही टाटा टेलीसर्विसेज और उसकी सूचीबद्ध सहायक टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड सितंबर व दिसंबर 2019 की तिमाही में एजीआर बकाए के लिए पूरा प्रावधान कर चुकी है।

बैंकिंग सूत्रों के मुताबिक, टाटा टेली के पास महज 200 करोड़ रुपये की नकदी है और उसे एजीआर बकाया चुकाने के लिए अपने प्रवर्तकों से मदद लेनी होगी। टाटा समूह पहले ही बैंक व सरकार का 60,000 करोड़ रुपये बकाए का भुगतान कर चुका है और अतिरिक्त भुगतान के साथ दूरसंचार में कुल 74,000 करोड़ रुपये का भुगतान हो जाएगा।

टाटा संस के पास क्या है विकल्प

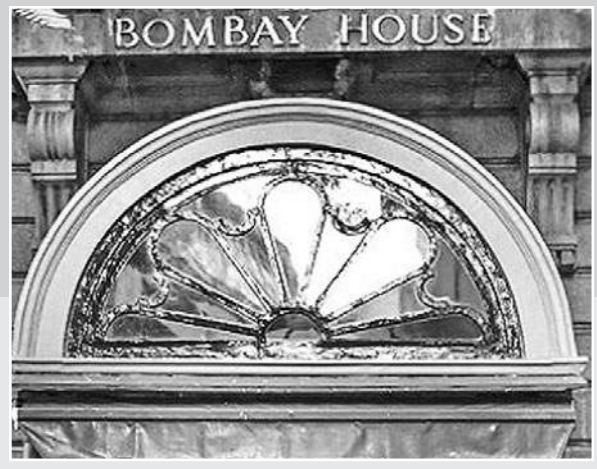

- दूरसंचार क्षेत्र का हालिया संकट टाटा संस की वित्तीय स्थिति पर चोट करेगा क्योंकि उसे या तो टीसीएस के शेयर बेचने होंगे या फिर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनी से मार्च तक ज्यादा लाभांश मांगना होगा
- टीसीएस में टाटा संस की हिस्सेदारी की कीमत शुक्रवार के बंद भाव के हिसाब से 5.9 लाख करोड़ रुपये बैठती है

टाटा संस ने इस पर टिप्पणी करने से मना कर दिया, लेकिन आंतरिक सूत्रों ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र का हालिया संकट टाटा संस की वित्तीय स्थिति पर चोट करेगा क्योंकि उसे या तो टीसीएस के शेयर बेचने होंगे या फिर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनी से मार्च तक ज्यादा लाभांश मांगना होगा।

दिलचस्प रूप से टाटा संस पिछले दो वित्त वर्ष से टाटा टेली में अपने निवेश को बट्टे खाते में डाल रही है और मार्च 2020 में समाप्त हो रहे मौजूदा वित्त वर्ष में भी उसे ऐसा करना होगा। टाटा संस ने वित्त वर्ष 2019 और वित्त वर्ष 2020 में टाटा टेलीसर्विसेज में 23,090 करोड़ रुपये लगाए, जिसके कारण उसका शुद्ध कर्ज 31 जुलाई 2019 के 27,840 करोड़ रुपये के मुकाबले बढ़कर 30,488 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। रकम लगाए जाने के बाद टाटा टेली अपना कर्ज 31 मार्च 2018 के 30,741 करोड़ रुपये के मुकाबले घटाकर 31 दिसंबर 2019 को 8,265 करोड़ रुपये पर लाने में कामयाब रही।

टाटा टेली के पास 31 दिसंबर 2019 को कम नकदी थी, ऐसे में टाटा संस को इस कमी की भरपाई के लिए आगे आना होगा। टाटा पर नजर रखने वालों ने कहा, टीसीएस को एक बार फिर टाटा संस को रकम देनी होगी ताकि वह सरकार को टाटा टेली का 14,000 करोड़ रुपये बकाया चुका सके। टाटा संस की तरफ से टीसीएस की 72.05 फीसदी हिस्से का एक भाग बेचकर या फिर कंपनी से ज्यादा लाभांश मांगकर यह काम हो सकता है। इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। टीसीएस में टाटा संस की हिस्सेदारी की कीमत शुक्रवार के बंद भाव के हिसाब से 5.9 लाख करोड़ रुपये बैठती है।

टाटा समूह ने वायरलेस टेलीफोनी कारोबार की यात्रा बिड़ला, एटीऐंडटी के साथ उद्यम के जरिये शुरू की थी। एटीऐंडटी और बिड़ला जब टाटा से निकल गई तो जनवरी 2005 में वह राष्ट्रीय स्तर पर दूरसंचार ऑपरेटर बन गई। कंपनी के पास 19 सर्किल में यूनिफाइड लाइसेंस था और नैशनल लॉन्ग डिस्टेंस लाइसेंस भी।

दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के बाद टाटा टेली अपनी प्रतिस्पर्धी भारती एयरटेल, वोडाफोन व आइडिया सेल्युलर से मुकाबला नहीं कर पाई। रिलायंस जियो के आने के बाद उसकी समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई और अंतत: उसने पिछले साल जुलाई में इस क्षेत्र को अलविदा कर दिया। भारती के साथ करार के मुताबिक, सभी ग्राहक, परिसंपत्तियां, स्पेक्ट्रम और टाटा टेली की कुछ देनदारी का भारती एयरटेल के साथ विलय हुआ है और टाटा टेली के पास कर्ज रह गया है। वायरलेस टेलिफोनी सेवा से बाहर निकलने के बाद टाटा टेली एंटरप्राइज बिजनेस, फिक्स्ड लाइन और ब्रॉडबैंड कारोबार में बनी हुई है।

स्पाइसजेट को दिसंबर तिमाही में 73.2 करोड़ रुपये का लाभ

बीएस संवाददाता/एजेंसियां
नई दिल्ली, 14 फरवरी

सस्ती विमानन सेवा स्पाइसजेट ने दिसंबर 2019 में समाप्त तिमाही के दौरान 73.2 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। विमानन कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा, 'एयर ट्रांसपोर्ट सेवा (विमानन) से एकल मुनाफा 115 करोड़ रुपये रहा। यह मुनाफा भारतीय लेखा मानक 116 के तहत 75.9 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा नुकसान के बाद है और इसके बिना मुनाफा 190.9 करोड़ रुपये होगा।' भारतीय लेखा मानक 116 का संबंध पट्टों से है। दिसंबर 2018 तिमाही में विमानन कंपनी ने 55.1 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। दिसंबर 2019 तिमाही में विमानन कंपनी का परिचालन राजस्व 47 फीसदी बढ़कर 3,674.1 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले की समान अवधि में स्पाइसजेट ने 2,486.8 करोड़ रुपये का परिचालन राजस्व दर्ज किया था। स्पाइसजेट के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अजय सिंह ने कहा कि मैक्स विमानों का परिचालन बंद होने से मुनाफे पर दबाव के बावजूद विमानन कंपनी ने हालिया तिमाही में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। पिछले साल बोइंग 737 मैक्स विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के मद्देनजर दुनिया भर में इन विमानों का परिचालन बंद कर दिया गया था। सिंह ने कहा, 'हम उम्मीद कर रहे थो कि मैक्स विमानों का परिचालन जनवरी 2020 से सुचारु हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ।' उन्होंने कहा, 'इन विमानों के परिचालन शुरू होने में देरी से निस्संदेह हमारी वृद्धि योजनाओं को झटका लगा है। इससे हमारी परिचालन क्षमता घट गई जबकि लागत में इजाफा हुआ है।' सिंह ने कहा कि विमानन कंपनी को लागत नियंत्रण के साथ-साथ लाभप्रदता में सुधार होने की उम्मीद है।

सन टीवी का कर पूर्व लाभ घटा

सन टीवी का कर पूर्व लाभ 31 दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही के दौरान घटकर 498.46 करोड़ रुपये रह गया जो एक साल पहले की समान अवधि में 542 करोड़ रुपये रहा था। तिमाही के दौरान कंपनी का राजस्व (मूवी वितरण से होने वाली आय को छोड़कर) मामूली बढ़कर 799.29 करोड़ रुपये हो गया जो दिसंबर 2018 में समाप्त तिमाही के दौरान 795.95 करोड़ रुपये रहा था।

गैमन इन्फ्रा का घाटा बढ़ा

गैमन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में एकीकृत आधार पर 51.24 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। कंपनी ने शुक्रवार को बीएसई को बताया कि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में उसे 21.16 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। इस दौरान उसकी कुल एकीकृत आय साल भर पहले के 131.58 करोड़ रुपये से कम होकर 79.36 करोड़ रुपये पर आ गई।

जीवीके पावर को 120 करोड़ रुपये का घाटा

जीवीके पावर ऐंड इन्फ्रास्ट्रक्चर को चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में एकीकृत आधार पर 120.06 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। कंपनी ने शुक्रवार को बीएसई को इसकी जानकारी दी। कंपनी ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में उसे 122.61 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। कंपनी ने कहा कि आलोच्य तिमाही के दौरान उसका एकीकृत राजस्व साल भर पहले के 1,109.28 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,156.15 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

श्री सीमेंट का कर पूर्व लाभ बढ़ा

कमजोर मांग परिदृश्य के बीच 31 दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही में श्री सीमेंट का कर पूर्व लाभ 2.82 फीसदी बढ़कर 409.76 करोड़ रुपये हो गया। तिमाही के दौरान कंपनी का राजस्व 3,146.01 करोड़ रुपये पर स्थिर रहा।

ओएनजीसी को कीमतों में नरमी का झटका

सरकारी तेल एवं गैस उत्खनन कंपनी ओएनजीसी को दिसंबर तिमाही में तेल एवं गैस कीमतों में नरमी और उत्पादन में गिरावट का दोहरा झटका लगा। तिमाही के दौरान कंपनी का एकल शुद्ध लाभ 49.8 फीसदी घटकर 4,152 करोड़ रुपये रह गया जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 8,263 करोड़ रुपये रहा था। तिमाही के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में 10 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई जबकि प्राकृतिक गैस की कीमतों में 4 फीसदी की कमी आई। इससे कंपनी का राजस्व दिसंबर तिमाही में 14.4 फीसदी घटकर 23,710 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान उसके तेल उत्पादन में 1 फीसदी की गिरावट रही जबकि गैस उत्पादन में 8.4 फीसदी की कमी आई। कंपनी ने उत्पादन में गिरावट का कोई कारण नहीं बताया है। *एजेंसियां*

एनएसई के खिलाफ सैट जाएगी एडलवाइस

समी मोडक
मुंबई, 14 फरवरी

एडलवाइस ब्रोकर डिफॉल्ट के मामले में नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के खिलाफ प्रतिभूति अपील ट्रिब्यूनल (सैट) में शिकायत करेगी। एनएसई ने अपनी क्लीयरिंग इकाई को एडलवाइस के सब-ब्रोकर वीराइज सिक्योरिटीज द्वारा जमानत के तौर पर रखी गई प्रतिभूतियों को लौटाने का निर्देश दिया था। एनएसई की पूर्ण स्वामित्व वाली क्लीयरिंग कॉरपोरेशन एनएसई क्लीयरिंग (एनएससीसीएल) ने एडलवाइस कस्टोडियल सर्विसेज (ईसीएसएल) को वीराइज के ग्राहकों से संबंधित प्रतिभूतियों को लौटाने का निर्देश दिया था। इन प्रतिभूतियों को जमानत के तौर पर ईसीएसएल के पास रखा गया था। लेकिन वीराइज द्वारा भुगतान में चूक किए जाने पर ईसीएसएल उन्हें भुनाने की तैयारी में थी।

ईसीएसएल ने जैसे ही उन प्रतिभूतियों को भुनाने की पहल की तो वीराइज के कुछ ग्राहकों ने ब्रोकरेज, एनएसई और बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) में उसके खिलाफ शिकायत कर दी। उनका कहना था कि उनकी प्रतिभूतियों को गलत तरीके से जमानत रख दी गई। एनएससीसीएल के निर्देश से एडलवाइस की योजना ठप हो गई।

वीडियोकॉन को एनसीएलटी से झटका

एजेंसियां
मुंबई, 14 फरवरी

नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने देश में चल रही ऋण शोधन प्रक्रिया में वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के विदेश में स्थित तेल और गैस कारोबार को शामिल करने का आदेश दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2016 के अंत में दिवालिया प्रक्रिया के लिए जिन 12 खातों को भेजा था उसमें वीडियोकॉन शामिल था। इस समूह पर कर्जदाताओं का सामूहिक रूप से 1 लाख करोड़ रुपये बकाया है। एनसीएलटी ने कहा है कि वीडियोकॉन समूह की अन्य व्यावसायिक संपत्तियों के साथ एक ही आर्थिक इकाई के रूप में व्यवहार करना सभी कर्जदाताओं के हित में है।

डीवीआर शेयरों में दिखी सुस्ती

सामान्य शेयरों व बेंचमार्क के मुकाबले कमजोर

सचिन मामबटा
मुंबई, 14 फरवरी

बजट पेश होने के बाद से डीवीआर (अलग या सीमित मताधिकार वाले शेयर) का प्रदर्शन व्यापक बाजार के मुकाबले कमजोर रहा है। बजट के बाद ऐसी प्रतिभूतियों पर औसत नुकसान 6.8 फीसदी रहा है जबकि बेंचमार्क एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स में 1.8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। डीवीआर शेयर वाली कंपनियों में टाटा मोटर्स, फ्यूचर एंटरप्राइजेज, जैन इरिगेशन सिस्टम्स और स्टाम्पिड कैपिटल शामिल है। डीवीआर का प्रदर्शन इन कंपनियों के सामान्य शेयरों के मुकाबले भी कमजोर रहा है, जो औसतन 3.4 फीसदी नीचे है।

जैन इरिगेशन का शेयर 2.8 फीसदी नीचे है जबकि उसके डीवीआर में 8.6 फीसदी की गिरावट आई है। टाटा मोटर्स का डीवीआर 5.1 फीसदी नीचे है जबकि उसके सामान्य शेयर में 4 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है। फ्यूचर एंटरप्राइजेज का सामान्य शेयर डीवीआर के मुकाबले बेहतर रहा है। उसके सामान्य शेयर में 2.3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई जबकि डीवीआर में 0.2 फीसदी की। स्टाम्पिज कैपिटल का सामान्य शेयर 7.5 फीसदी नीचे है, वहीं डीवीआर में 9.5 फीसदी की गिरावट आई है।

डीवीआर के साथ मोटे तौर पर सामान्य शेयर के मुकाबले मताधिकार कम होता है। लेकिन ऐसी प्रतिभूतियां निवेशकों को ज्यादा लाभांश की पेशकश करती है। बजट में कहा गया है कि इस लाभांश पर अब निवेशकों को कर चुकाना होगा। पहले 20.56 फीसदी की एकसमान दर (उपकर व अधिभार समेत) लागू थी। निवेशकों को लाभांश चुकाने से पहले कंपनियां लाभांश वितरण कर की कटौती करती थी। निवेशकों को अब इस पर कर चुकाना होगा। उच्च कर स्लैब के दायरे वाले निवेशकों को इस पर 42.7 फीसदी चुकाना पड़ सकता है।

ऐसा तब हुआ जबकि हाल में पाया गया कि डीवीआर से तकनीकी कंपनियों समेत कई तरह की फर्मों को पूंजी की जरूरत पूरी करने में मदद मिल सकती है।

डीवीआर और भारतीय संदर्भ में उसे लागू करने के मामले पर मार्च 2019 में जारी चर्चा पत्र में कहा गया है, यह खास तौर से तकनीकी फर्मों के लिए प्रासंगिक है, जिसके पास हल्की परिसंपत्ति का मॉडल है और कर्ज की काफी कम या कोई जरूरत नहीं होती। इन फर्मों को हालांकि सिर्फ इक्विटी के जरिए आगे बढ़ना होता है, जो प्रवर्तकों/संस्थापकों की हिस्सेदारी कम करता है और इस तरह से नियंत्रण घटता है। ऐसे मामलों में कारोबार में संस्थापक का हित व नियंत्रण बनाए रखना सभी शेयरधारकों के लिए अहम होता है।

बाजार नियामक सेबी ने जून में डीवीआर इश्यू के नियमों को मंजूरी दी। ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई डायरेक्ट के शोध प्रमुख पंकज पांडे ने कहा कि कंपनी विशेष के मसले भी डीवीआर शेयर वाली फर्मों से भविष्य में संभावित लाभांश की दिशा तय कर सकते हैं। अगर निवेशकों को लगेगा कि कम लाभांश मिलने वाला है तो इस प्रतिभूति का प्रदर्शन कमजोर रह सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतिभूतियों के धारक एचएनआई पर कराधान का असर पड़ सकता है।

सरकार बजट में बदलाव को तैयार

वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 2 दिन में आ सकते हैं विवाद से विश्वास विधेयक को लेकर स्पष्ट नियम

इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 14 फरवरी

उद्योगों की चिंता दूर करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के प्रस्तावों में बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय घोषणाओं से इतर भी कदम उठाने को इच्छुक है, जिससे कि अर्थव्यवस्था में तेजी लाई जा सके।

विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ चर्चा के बाद आज उन्होंने कहा, 'बजट के प्रस्तावों में जरूरत के मुताबिक बदलाव और इससे इतर भी जरूरत पड़ने पर कदम उठाए जा सकते हैं। बजट के बाद ऐसा करने को हम इच्छुक हैं।'

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि वित्त मंत्रालय प्रत्यक्ष कर समाधान योजना के लिए 2 दिन के भीतर विस्तृत नियम लाएगी, जिससे इस योजना के मुताबिक कर विवाद सुलझाने के इच्छुक लोगों के लिए स्थिति साफ हो सके। बजट में बदलाव की बात ऐसे समय की गई है, जब अगले महीने संसद में काम शुरू होने पर वित्त विधेयक पर चर्चा होने वाली है। उद्योग जगत ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी), बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट(इनविट) लाभांश कर, इंप्लाई स्टॉक ऑप्शन (ईसॉप), रियल एस्टेट के अलावा अन्य क्षेत्रों में कर को लेकर स्पष्टता की मांग की है।

संशोधित प्रत्यक्ष कर समाधान या विवाद से विश्वास विधेयक अभी संसद में पेश किया जाना है और इसके बाद उसे लागू किया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि विधेयक के तहत नियम अधिसूचना के रूप में नहीं होंगे।

उन्होंने कहा कि विस्तृत ब्योरे से तस्वीर साफ हो सकेगी कि संसद द्वारा पारित विधेयक के बाद अधिसूचना में क्या होगा।

उन्होंने कहा, 'एक या दो दिन में हम इस पर बगैर पत्र लाए स्थिति साफ करेंगे, क्योंकि संसद में इसे पारित नहीं किया गया है।'

सरकार बजट के बाद के कदम उठाने को तैयार

- बजट प्रस्तावों में जरूरत के मुताबिक बदलाव और इससे इतर भी जरूरत पड़ने पर कदम उठाए जा सकते हैं
- प्रत्यक्ष कर से संबद्ध विवादों के समाधान को लेकर लाई गई विवाद से विश्वास योजना पर वित्त मंत्रालय जल्दी ही विस्तृत ब्योरा उपलब्ध कराएगा।
- 2020-21 का बजट ऐसा है जिसका इक्विटी, बांड और मुद्रा बाजार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा

उन्होंने डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी सहित सलाहकारों को कहा कि उन्हें यह देखने और अपने क्लांइट को इनके बारे में बताने के लिए वक्क्त है। वित्त मंत्री ने सलाहकारों से कहा, 'विधेयक पारित होने के पहले आपको 30 दिन या 3 सप्ताह मिलेंगे।'

हाल ही में कैबिनेट ने विधेयक के विस्तार की संभावना को हरी झंडी दी है, जिससे कि विवाद से विश्वास को और ज्यादा आकर्षक बनाया जा सके। इसके दायरे में पंचाटों और कर्ज वसूली ट्रिब्यूनल में लंबित याचिकाएं आएंगी। इस योजना में पुनरीक्षण और कम मूल्य के विवाद शामिल होंगे।

कैबिनेट ने उन करदाताों की विवादित राशि भी घटाकर आधी कर दी थी, जिन्हें उनके पक्ष में आदेश मिले हैं, लेकिन आयकर विभाग ने उन आदेशों को चुनौती दी थी।

सीतारमण ने पहले ही कर मामलों में विवाद के समाधान के लिए लोकसभा में विधेयक पेश कर दिया है। यह राशि 9.3 लाख करोड़ रुपये है। इस योजना में मामले के निपटान पर ब्याज, जुर्माने और दंड से छूट दी गई है।

इसके पहले यह आयुक्त (अपील) आयकर अपील न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के पास 31 जनवरी 2020 तक लंबित ममलों तक सीमित थी। अब अगर 31 मार्च तक बकाया कर का भुगतान कर दिया जाता है तो पूरी तरह से ब्याज व जुर्माना माफ किया जाएगा। इसके अलावा उसके बाद 10 प्रतिशत विवादित राशि का भुगतान भी कर दिया जाएगा।

वित्त मंत्री ने परिचर्चा में शामिल पेशेवरों को आश्वस्त किया कि उनका मंत्रालय सुझावों पर गौर करेगा। इससे पहले, सीतारमण मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में इसी प्रकार की परिचर्चा कर चुकी हैं। बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत शामिल थे। इसके अलावा वित्त मंत्रालय के सचिव भी इसमें उपस्थित थे।

अहम परियोजनाओं पर ध्यान

श्रेया जय
नई दिल्ली, 14 फरवरी

भारतीय रेल राष्ट्रीय महत्त्व की चल रही परियोजनाओं के काम में तेजी लाने के लिए उनके लिए प्राथमिकता के आधार पर वित्तपोषण करेगी। खासकर उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन पर भीड़ कम करने के लिए काम किया जा रहा है। रेलवे ने पूरी होने के करीब वाली परियोजनाओं को पूर्ण बजट अनुदान और शुरुआती चरण वाली परियोनजाओं का चरणबद्ध वित्तपोषण करेगी।

रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने कहा कि इससे उन परियोजनाओं के काम में तेजी आएगी, जो कंजेशन घटाने के हिसाब से अहम हैं। कंजेशन कम करने के लिए 58 परियोजनाएं चिन्हित की गई हैं, इनमें से 8 शुरू हो चुकी हैं और उनमें से 7 चालू वित्त वर्ष की हैं।

रेवले को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 70,000 करोड़ रुपये बजट आवंटन किया गया है, जबकि पूंजीगत व्यय की राशि 1.61 लाख करोड़ रुपये है।

यादव ने कहा, 'करीब 89 प्रतिशत परियोजनाओं को औसतन प्रति परियोजना 140 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 11 प्रतिशत परियोजनाओं को प्रति परियोजना औसत आवंटन 1,000 करोड रुपये है। सबसे ज्यादा 3,8000 करोड़ रुपये आवंटन उधमपुर बारामूला रेल लाइन (यूबीआरएल) के लिए किया गया है।'

उन्होंने कहा कि यूबीआरएल परियोजना जून 2022 में पूरी होने की उम्मीद है, जिसकी निगरानी प्रधानमंत्री कार्यालय कर रहा है, जिससे इसे तेजी से पूरा किया जा सके। पहले इसे 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन परियोजना में देरी हो रही है।

रेलवे की नई नीति

272 किलोमीटर की उधमपुर बारामुला रेल लाइन में कटरा और बनिहाल के बीच करीब 111 किलोमीटर रेल खंड पूरा नहीं हुआ है। इसके लिए 21,653 करोड़ रुपये आवंटन किया गया है। रेल मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि 6,000 करोड़ रुपये लागत से 161 किलोमीटर रेलखंड का काम पूरा कर लिया गया है, जिसमें 97 किलोमीटर लंबी सुरंग है। इस परियोजना में चिनाव नदी पर 359 मीटर ऊंचा पुल भी होगा, जिसके बारे में अधिकारियों का दावा है कि यह एफिल टॉवर (324 मीटर) से ऊंचा होगा। चिनाव रेल पुल की अनुमानित लागत 1,250 करोड़ रुपये है, जो घाटी का प्रवेश द्वार होगा और इससे घाटी शेष भारत से रेल मार्ग से जुड़ जाएगी और इससे तैयार माल को तेजी से भेजे जाने और सुरक्षा बलों की तेज आवाजाही में मदद मिलेगी। इनके अलावा राष्ट्रीय महत्त्व की 4 और परियोजनाएं हैं, जिन्हें अगले 3 साल में पूरा किया जाना है। इसमें मिजोरम में 51 किलोमीटर लंबी सैरंग बैबेली ब्रॉड गेज लाइन शामिल है, जिस पर 5,021 करोड़ रुपये लागत आएगी। इसके 12,524 करोड़ रुपये लागत की 83 किलोमीटर लंबी अलावा दीमापुर कोहिमा लाइन, सिक्किम की 4,000 करोड़ रुपये लागत से प्रस्तावित सिवोक-रंगपो रेल लाइनें शामिल हैं।

यादव ने कहा कि बुनियादी ढांचा पर रेलवे द्वारा ध्यान बढ़ाने की वजह से अपेक्षित परिणाम आए हैं। उन्होंने कहा कि 2009 से 2014 के बीच जहां 7,599 किलोमीटर रेल लाइनें बनीं, वहीं 2014-19 के बीच 13,124 किलोमीटर लंबी लाइनें बनीं और इसमें 173 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

संक्षेप में

3 हवाईअड्डों के लिए 50 साल का समझौता

अदाणी इंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) ने शुक्रवार को अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलूरु सहित 3 हवाईअड्डों को विकसित करने व उनके 50 साल के परिचालन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता किया है। कंपनी ने शेयर बाजार को यह जानकारी दी है। यह समझौता एएआई और एईएल की पूर्ण मालिकाना वाली सहायक इकाइयों अदाणी अहमदाबाद इंटरनैशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, अदाणी लखनऊ इंटरनैशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और अदाणी मंगलूरु इंटरनैशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बीच हुआ है। *बीएस*

श्याओमी के खिलाफ दायर याचिका खारिज

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुनाफाखोरी निगरानीकर्ता ने चीन की स्मार्टफोन विनिर्माता श्याओमी को बड़ी राहत दी है। मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (एनएए) ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी पॉवर बैंक पर घटी दरों का लाभ ग्राहकों को नहीं दे रही है। *बीएस*

जनवरी में लगातार छठे महीने निर्यात गिरा

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 14 फरवरी

जनवरी में लगातार छठे महीने निर्यात में कमी आई है। विदेशी मुद्रा कमाने वाले प्रमुख क्षेत्रों जैसे इंजीनियरिंग के सामान, आभूषण और टेक्सटाइल के निर्यात में गिरावट जारी है। हालांकि पेट्रोलियम निर्यात में तेजी आई है।

वाणिज्य विभाग की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी में निर्यात 1.6 प्रतिशत घटा है, जो दिसंबर के 1.8 प्रतिशत गिरावट की तुलना में कम है। वित्त वर्ष 2019-20 के पहले 10 महीने के दौरान निर्यात में गिरावट का रुख है। जनवरी तक कुल निर्यात 265.3 अरब रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 1.9 प्रतिशत कम है।

वहीं इस दौरान आयात में भी गिरावट आई है। जनवरी में आयात 0.7 प्रतिशत घटा है, जो दिसंबर के 8.9 प्रतिशत गिरावट की तुलना में बहुत कम है। कुल मिलाकर भारत ने अप्रैल-जनवरी के दौरान 399 अरब डॉलर का आयात किया है, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 8.1 प्रतिशत कम है। लेकिन जनवरी में व्यापार घाटा बढ़कर 15 अरब डॉलर हो गया, जो नवंबर में 11.2 अरब डॉलर था। इक्रा में मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नैयर ने कहा, 'घाटा बढ़ने की मुख्य वजह कच्चे तेल के आयात में बढ़ोतरी है।'

सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि जनवरी में निर्यात 25.0 अरब डॉलर रहा है और निर्यात के 30 प्रमुख क्षेत्रों में से 17 में गिरावट देखी गई है, जो पहले महीने के 19 की तुलना में कम है। देश के सबसे बड़े एकल निर्यात वाले पेट्रोलियम क्षेत्र के निर्यात में तेजी वापस लौटी है और यह 2 प्रतिशत बढ़ा है। पिछले महीने इसमें 8 प्रतिशत गिरावट दर्ज हुई थी।

अमेरिकी डेयरी को राहत नहीं

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 14 फरवरी

सरकार ने उन रिपोर्टों को नकार दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार ने अमेरिका के साथ एक सीमित व्यापार सौदे पर चल रही चर्चा के हिस्से के तौर पर अमेरिकी कंपनियों के लिए अपने पोल्ट्री और डेरी बाजारों को खोलने की पेशकश की है।

गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि भारत ने अंतत: अमेरिका से मंगाए गए मुर्गे के टांगों के लिए अपने यहां बाजार पहुंच की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही अमेरिकी टर्की पक्षी और ब्लूबेरी तथा चेरी जैसे कृषि उत्पादों को बाजार पहुंच देने की अनुमति दी गई है। रिपोर्टों में कहा गया था कि भारत सरकार ने यह कदम इसी महीने होने जा रही अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की यात्रा को मद्देनजर रखते हुए उठाया है। हालांकि अधिकारियों ने इन दावों को खारिज कर दिया।

भारत अमेरिका कारोबारी वार्ता

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'करीब एक दशक से दोनों देशों के बीच विवाद की मुख्य वजह मुर्गे की टांग रही है। लेकिन मुर्गे की टांग आयात करने की हमारी मौजूदा व्यवस्था पूरी तरह विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों मुताबिक है और बाजार पहुंच की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है।' उस अधिकारी ने कहा डेरी को लेकर भी कोई बातचीत नहीं हुई है।

आरंभ में 2015 में डब्लयूटीओ में अमेरिका की ओर से दायर किए गए एक मुकदमे को हारने के बाद भारत सरकार ने 2017 में अनुपालन दल के प्रतिष्ठान को सुरक्षित किया था लेकिन अंतत: 2018 में अमेरिकी पोल्ट्री को पहुंच की छूट दी थी जब उसकी पहली खेप आई थी।

भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा सबसे बड़ा मुर्गीपालक और तीसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक देश है।

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के मुताबिक भारत ने दुनिया भर में 2018-19 के दौरान 9.85 करोड़ डॉलर मूल्य के 5.4 लाख मीट्रिक टन पोल्ट्री उत्पादों का निर्यात किया था।

बैंकों के विलय पर संशय

पृष्ठ 1 का शेष

इस महीने हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की दो बैठकों में बैंकों के विलय की योजना को मंजूरी नहीं दी गई। इससे विल की प्रक्रिया में शामिल शीर्ष बैंकर चिंतित हैं। उन्हें लगता है कि 1 अप्रैल की समयसीमा तक बैंकों के बहीखाते और शेयरों का विलय करना मुश्किल है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल 30 अगस्त को सरकारी बैंकों के सबसे बड़े विलय की घोषणा की थी। इसके मुताबिक पंजाब नैशनल बैंक, ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मिलाकर देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बनाया जाएगा। केनरा बैंक सिंडिकेट बैंक का अधिग्रहण करेगा जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के साथ मिलाया जाएगा।

इसी तरह इंडियन बैंक का इलाहाबाद बैंक में विलय होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक का विलय 1 अप्रैल, 2019 को प्रभाव में आया था। इन तीन बैंकों के विलय का फैसला सितंबर, 2018 में किया गया था और सरकार ने इस बारे में 2 जनवरी, 2019 को अधिसूचना जारी की थी। उसी दिन तीनों बैंकों के बोर्ड ने विजया बैंक और देना बैंक के शेयरधारों के लिए शेयरों की अदलाबदली का अनुपात घोषित किया था। लेकिन 10 सरकारी बैंकों के विलय के मामले में केंद्रीय मंत्रिमंडिल ने अब तक इस योजना को मंजूरी नहीं दी है।

विलय प्रक्रिया में शामिल एक बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी ने कहा, 'अधिसूचना जारी होने के बाद बैंकों को प्रक्रिया पूरी करने में 40 से 45 दिन का समय लगेगा। सरकार ने अब तक इस बारे में अधिसूचना जारी नहीं की है, इसलिए 1 अप्रैल की समयसीमा मुश्किल लगती है।'

प्रक्रिया के मुताबिक सरकार को विलय की योजना संसद में पेश करनी होगी। अधिसूचना जारी होने के बाद बैंकों के निदेशक मंडल की शेयरों की अदलाबदली के अनुपात को मंजूरी देने के लिए बैठक होगी।

विदेश यात्रा से कर वापस लिए जाने की मांग

अनीश फडणीस
मुंबई, 14 फरवरी

ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन आफ इंडिया (टीएएआई) ने विदेश जाने वाले यात्रियों से स्रोत पर 5 प्रतिशत आयकर लगाने के बजट प्रस्ताव को वापस लेने का अनुरोध किया है। संगठन का कहना है कि इससे विदेशी ट्रैवल फर्मों को अनुचित लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी गई याचिका में टीएएआई ने कहा है, 'भारत के बाहर काम करने वाले अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियां और विदेशी टूर ऑपरेटर बगैर जीएसटी या कर संग्रह किए बगैर सीधे यात्रियों के लिए एयर टिकट, होटल और टूर पैकेज बुक कर रहे हैं। यहां तक कि वे स्रोत पर कर का भी संग्रह नहीं करते हैं। इसकी वजह से भारत की कंपनियों का कारोबार विदेशी ट्रैवल कंपनियों के पास जा रहा है, जिसकी वजह से भारत सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है।' सरकार के इस प्रस्ताव को लागू किए जाने का असर 60,000 ट्रैवल एजेंसियों पर पड़ेगा, जिनमें 20 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

सरकार ने विदेश के टूर पैकेज पर 5 प्रतिशत टीसीएस का प्रस्ताव किया है, जिसका मकसद राजस्व वसूली में गड़बड़ी को रोकना है। हालांकि इस अतिरिक्त कर से यात्रियों की नकदी बोझ में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इस कर राशि को व्यक्ति के कुल कर देनदारियों में समायोजित कर दिया जाएगा।

ट्रैवल एजेंटों का कहना है कि टीसीएस लगाए जाने से स्थानीय कंपनियों के अनुपालन लागत में बढ़ोतरी होगी जो कारोबार सुगमता के सिद्धांत के विपरीत है।

बीपीसीएल, शिपिंग कॉर्प, कॉनकॉर के लिए शीघ्र अभिरूचि पत्र

अरूप रायचौधरी
नई दिल्ली, 14 फरवरी

केंद्र सरकार भारत पेट्रोलियम में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए संभावित खरीदारों को आमंत्रित करने के लिए कुछ ही दिनों में अभिरूचि पत्र (ईओआई) और प्राथमिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) जारी कर सकती है। इसके बाद कंटेनर कॉर्प और फिर शिपिंग कॉर्प में रणनीतिक बिक्री के लिए ईओआई और पीआईएम लाया जाएगा। बिजनेस स्टैंडर्ड को पता चला है कि मार्च के मध्य तक इन तीनों कंपनियों के लिए ईओआई और पीआईएम जारी कर दिया जाएगा।

इसका मतलब है कि 1 अप्रैल को जब वित्त वर्ष 2020-21 की शुरुआत होगी तब तक इन कंपनियों के केंद्र की हिस्सेदारी बिक्री की प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी होगी। वित्त मंत्रालय के निवेश एवं सार्वजनिक वित्त प्रबंधन विभाग (दीपम) के वरिष्ठ अधिकारी इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि केंद्र सरकार आगामी वित्त वर्ष की पहली छमाही में बीपीसीएल, कॉनकॉर, शिपिंग कॉर्प और एयर इंडिया का निजीकरण करने में कामयाब होगी।

यही बात आज दीपम के सचिव तुहिनकांत पांडे की प्रतिक्रिया में नजर आई। वह नीति आयोग में सरकारी अधिकारियों और वित्त क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ बजट के बाद की बैठक में शामिल होने आए थे। उन्होंने कहा कि चार कंपनियों के निजीकरण की प्रक्रिया वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही में पूरी कर ली जाएगी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'कुछ ही दिनों में बीपीसीएल के लिए ईओआई जारी कर दी जाएगी। रणनीतिक बिक्रियों के लिए केवल अल्टरनेटिव मैकेनिज्म से मंजूरी लेना बाकी है।' सौदे में नुमालीगढ़ रिफाइनरी को छोड़कर सभी संपत्तियों में बीपीसीएल की हिस्सेदारी को शामिल किया जाएगा। उस अधिकारी ने कहा कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी को सौदे से बाहर रखा गया है।

नई रणनीति

- मार्च के मध्य तक बीपीसीएल, कॉनकॉर, शिपिंग कॉर्प के लिए आएगा ईओआई
- ई-नीलामी के जरिये विनिवेश वाली पहली कंपनी हो सकती है बीपीसीएल या एयर इंडिया
- बीपीसीएल, कॉनकॉर, शिपिंग कॉर्प, एयर इंडिया की रणनीतिक बिक्री वित्त वर्ष21 की पहली छमाही तक पूरी होने को लेकर सरकार आश्वस्त

अधिकारी ने कहा, 'कॉनकॉर के सौदे के लिए केवल इस बात पर काम करना बाकी है कि भारतीय रेलवे संभावित खरीदार को किन शर्तों पर जमीन का पट्टा देगी। एक बार यह स्पष्ट होते ही ईओआई जारी कर दिया जाएगा। इसमें वे सारी जानकारियां और उनके आधार पर कॉनकॉर का मूल्यांकन शामिल होगा।' इसके बाद 15 मार्च तक शिपिंग कॉर्प का ईओआई और पीआईएम जारी किए जा सकते हैं। उस अधिकारी ने कहा कि कंपनी के लिए रोड शो का काम अभी भी लंबित है। इसके लिए संभावित गंतव्यों में सिंगापुर, दुबई और यूरोप के बड़े शिपिंग उद्योग गंतव्य शामिल हैं।

इसके अलावा, बीपीसीएल या एयर इंडिया वह पहली कंपनी होगी जिसकी हिस्सेदारी बिक्री नई ई-बोली प्लेटफॉर्म के जरिये की जाएगी। एक दूसरे अधिकारी ने बताया कि यह प्लेटफॉर्म विनिवेश के लिए बनाया गया है। ऑनलाइन माध्यम को अपनाने और कागजी बोली से दूरी बनाने से प्रक्रिया को ज्यादा सुदृढ़ और पारदर्शी बनने की उम्मीद है।

बहरहाल, अधिकारियों ने कहा कि कोरोनावायरस के डर से सुदूर पूर्व देशों में रोड शो रद्द होने से भी चालू वित्त वर्ष (2019-20) के लिए संशोधित विनिवेश योजनाएं पटरी से नहीं उतरेगी। आईआरएफसी लिमिटेड के लिए आरंभिक सार्वजनिक निर्गम और एनएमडीसी लिमिटेड तथा सेल के लिए बिक्री की पेशकश की खातिर रद्द किए गए रोड शो को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये किया जाएगा और ये तीनों सार्वजनिक इश्यू 31 मार्च से पहले पूरे हो जाने की उम्मीद है।

2020-21 के लिए 2.10 लाख करोड़ रुपये का भारी भरकम विनिवेश लक्ष्य रखा गया है। यह 2017-18 में दीपम द्वारा हासिल किए गए 1 लाख करोड़ रुपये से दोगुने से अधिक है। 2019-20 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.05 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया था। इसे हालिया केंद्रीय बजट में संशोधित कर 65,000 करोड़ रुपये कर दिया गया था।

दीपम के अधिकारियों ने कहा कि वित्त वर्ष 2020 के लिए अब तक करीब 35,000 करोड़ रुपये हासिल किए जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2021 के लिए निर्धारित 2.1 लाख करोड़ के विनिवेश लक्ष्य में से करीब 90,000 करोड़ रुपये आईडीबीआई बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम जैसे वित्त क्षेत्र की कंपनियों में सरकारी की हिस्सेदारी बिक्री से प्राप्त होगी।

बीएस सूडोकू 3665 | परिणाम संख्या 3664

6	5			3			1	
		1		7	8			
3	9	8				7	5	4
7		2	4	5				1
5								9
9				6	3	5		7
2	4	3				1	7	8
			3	4		2		
	6			2			3	5

9	6	8	7	4	5	2	1	3
4	7	3	2	9	1	5	8	6
5	1	2	3	6	8	9	4	7
6	4	1	9	5	2	7	3	8
8	3	9	4	1	7	6	5	2
7	2	5	6	8	3	4	9	1
3	5	6	8	2	4	1	7	9
1	9	7	5	3	6	8	2	4
2	8	4	1	7	9	3	6	5

कैसे खेलें? हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

बहुत आसान ★☆☆☆☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2020/2030, जौ 1760/1780, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2200/2250, सरसों 4150/4200, तिल सफेद 8900/9000, सोया (टीन) 1500/1525, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1400/1500,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2040/2050, गेहूं शरबती 2825/2925, चावल शरबती सेला 3600/3650, स्टीम 4100/4150, लालमती 3050/3100, चावल (सोना) 2600/2650,

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1320, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1388, फ्लैक 1340, डीएमओ 965, टरपीन लैस बोल्ड 1410

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू 1000/1065, खुरपा 980/1000,चाकू 1030/1080, रसकट 900/930, शक्कर 1100/1125, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3295, बुंदकी 3270, बुढ़ाना 3300, शामली 3240,

हापुड़
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3500/3600, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 950/970, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4200, खल: सरसों 2150/2250, बिनौला 2250/2400, चना छिलका 2100/2150,

जयपुर
अनाज: चावल डीबी 5000/5200, गेहूं (मिल) 2120/2125, मक्की 1975/1980, बाजरा 1740/1750, जौ 1775/1800, ग्वार लूज 3725/3750, ज्वार कैटलफीड 2400/2500, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 4240/4250,

श्रीगंगानगर
गेहूं (देरी) 2000/2100, ग्वार 3600/3650, जौ 2040/2050,

जोधपुर
गेहूं 2050/2100, जौ 1800/1825, पोपकोन मक्की 4400/4500, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 3900/3950, ग्वारगम 6800/6900, बाजरा (गुजरात) 1800/1825, बाजरा (जयपुर) 1800/1825, चना 4100/4200, काबली चना 4900/6000, मूंग 7000/7200,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्याइंट)104, राइसब्रान (अखाद्य) 101, खल सरसों 1870, डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 1050, लाल 1050, कंटीन्यूअस 1120,

लुधियाना
दाल-दलहन: राजमां चित्रा 8300/9000, अरहर दाल 7500/8000, उड़द साबुत 7400/8500, उड़द धोया 9200/9800, छिलका 8700/9400, दाल मसूर 6000/6300, चनादाल 5350/5450,

अमृतसर
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 5750/5800, सेला 5150/5200, शरबती साधारण सेला 3650/3675, शरबती स्टीम 3950/4000,चावल 1509 सेला 4800/4900, धान: शरबती 2000/2050,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 3990/4035, हरियाणा 3975/3995, राजस्थान 3930/4000, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2400/2500, सरसों खल 2025/2030,

फाजिल्का
गेहूं 2040/2050, सरसों 3900/3970 रुई (प्रति मन): (जे-34) 4000/4050, कपास देशी 4300/4400, कपास नरमा (क्विं.) 5100/5400, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2150/2250,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2040/2060, चावल परमल कच्चा 2325/2365, से ला 2260/2310, मक्की यूपी 1975/2000, दाल उड़द छिलका 8700/9800, चना देशी 4725/4775, दाल चना 5000/5100, काबली चना 5000/6000, राजमां चित्रा पुणे 7200/8700,चीन 8700/9100, शर्मिली 6200/7200,

करनाल
गेहूं दड़ा 2035/2045, बासमती चावल 6050/6150, धान 1121 नं. 2700/2750, पूसा 1509 धान 2500/2550, शरबती धान 2000/2040, सेला (1509 नं.) चावल 4800/4825, स्टीम 5800/5900,

हिसार
ग्वार 3650/3700, जौ 1840/1850, सरसों 3800/3850, मूंग 7100/7200, गेहूं 2050/2065,

जींद
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूं 2100/2130, आटा (प्रति 44 किलो) 1040/1060, मैदा 1140/1160, देशी घी (एक ली/जार) 360/460, रिफाइंड (टीन) 1480/1500,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 3850/3900, खल बिनौला मोटी 2100/2200, बिनौला 2600/3100, सरसों तेल 8600/8700, गेहूं 2000/2100, ग्वार 3700/3750, बाजरा 1725/1750 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 310

कम क्यों हुए करदाता ?

प्रधानमंत्री ने इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि देश में केवल 1.5 करोड़ लोग ही कर चुकाते हैं। उनकी शिकायत वाजिब है क्योंकि इससे ज्यादा लोग तो एक वर्ष में दोपहिया वाहन खरीद लेते हैं। देश में कुल मिलाकर 18 करोड़ दोपहिया वाहन हैं। सबसे सस्ता स्कूटर भी 50,000 रुपये का मिलता है और ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड तो 65,000 रुपये से भी अधिक में मिलते हैं। ऐसे में यह उम्मीद करना गलत नहीं है कि अगर कोई स्कूटर या मोटर साइकिल रखने लायक पैसे कमाता है तो उसे आय कर चुकाना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि 10 फीसदी से भी कम लोग आय कर देते हैं।

यानी नरेंद्र मोदी की शिकायत सही है लेकिन यह शिकायत उन्हें नहीं करनी चाहिए। मोदी जहां करदाताओं की कम तादाद के लिए नागरिकों को दोष देते हैं और उन्हें ईमानदारी से कर चुकाने को कहते हैं, वहीं उन्हें खुद को और 2019 के वित्त मंत्री को भी दोष देना चाहिए जिन्होंने लोक सभा चुनाव वाले वर्ष में 5 लाख रुपये तक की आय अर्जित करने वाले सभी व्यक्तियों को आय कर चुकाने से मुक्त कर दिया था। जानकारी के मुताबिक उनकी घोषणा के चलते तीन चौथाई करदाता कर दायरे से बाहर हो गए। चुनाव के पहले ऐसे कदम उठाए जाना स्वाभाविक है लेकिन मोदी को यह समझना चाहिए कि करदाताओं की संख्या 6 करोड़ से घटाकर 1.5 करोड़ करने का काम उनका ही था।

इस विषय में अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं काफी जानकारीपरक हैं। अमेरिका में लोग 12,000 डॉलर की आय के स्तर पर आयकर चुकाना शुरू कर देते हैं। यह गरीबी रेखा के स्तर से लगभग समांतर होता है। यदि कोई युगल एक साथ रिटर्न दाखिल करता है तो उसे कर चुकाने के पहले उक्त आय का दोगुना कमाना होता है। अहम बात यह है कि चार सदस्यों वाले परिवार के लिए आयकर चुकाने की सीमा 25,000 डॉलर है। व्यापक तौर पर देखा जाए तो यह भी ऐसे परिवार की गरीबी रेखा के स्तर के आसपास है। इन आंकड़ों के पीछे दलील है। एक सिद्धांत यह नजर आता है कि एक बार गरीबी रेखा के ऊपर जाने के बाद आपको कर चुकाना चाहिए। ब्रिटेन में भी ऐसा ही है। वहां गरीबी की कई परिभाषाएं हैं लेकिन कर चुकता करने का सिलसिला कमोबेश गरीबी रेखा के स्तर की आय से शुरू होता है जो करीब 12,000 पाउंड है।

साप्ताहिक मंथन

टी. एन. नाइनन

इसकी तुलना भारत से करें तो हमारे यहां कर चुकाने की सीमा किसी परिवार के गरीबी रेखा के स्तर पर आय के गुणक से तय होती है। औसतन चार लोगों के परिवार में यह उनकी औसत आय से दोगुना यानी करीब 2.5 लाख रुपये है। एक वर्ष पहले तक कर सीमा का स्तर यही था लेकिन उसके बाद इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया। ऐसे में प्राथमिक समस्या करदाताओं में नहीं बल्कि कर नियमों में है जिन्होंने कर चुकाने की सीमा को बहुत ऊंचा कर दिया। यदि कर सीमा को पुराने स्तर पर कर दिया जाए तो कर चुकाने वालों की तादाद स्वत: चार गुना हो जाएगी।

कर दरों में भी समस्या है। भारत में कर की शुरुआत 5 फीसदी के स्तर से होती है। जबकि ब्रिटेन में सबसे निचली कर दर 20 फीसदी है। अमेरिका में यह संघीय स्तर पर 10 फीसदी तथा विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है। यहां ताजा नियमों के मुताबिक 20 फीसदी की दर से कर चुकाने के पहले 10 लाख रुपये के आय स्तर पर पहुंचना होता है यानी चार लोगों के औसत परिवार की औसत सालाना आय का चार गुना। सच यह है कि देश में आयकर का स्तर काफी ऊंचे आय स्तर पर और अस्वाभाविक रूप से कम दर पर शुरू होता है।

सरकार की अन्य नाकामी की बात करें तो वह संबंधित व्यक्ति के कर रिटर्न को उसके व्यय और बचत की आदत, विदेश यात्राओं, वाहन स्वामित्व और बिजली की खपत के स्तर से दोबारा मिलान या जांच में चूक करती है। चूंकि उच्च मूल्य के ज्यादातर लेनदेन में स्थायी खाता संख्या देना जरूरी है इसलिए प्रभावी ढंग से जांच होने पर अधिकांश कर वंचक पकड़े जाने चाहिए थे। यह सच है कि नोटबंदी और अन्य उपायों के बाद कर रिटर्न दाखिल करने वालों की तादाद बढ़ी है लेकिन कुल मिलाकर आज हालात निराशाजनक हैं।

ऐसे में प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वह सही है लेकिन यह समस्या उनकी सरकार की खड़ी की हुई है। हालात को बदलना भी सरकार के हाथ में है। बशर्ते कि उसमें मुखर मध्य वर्ग के विरोध की अनदेखी करने का माद्दा हो।

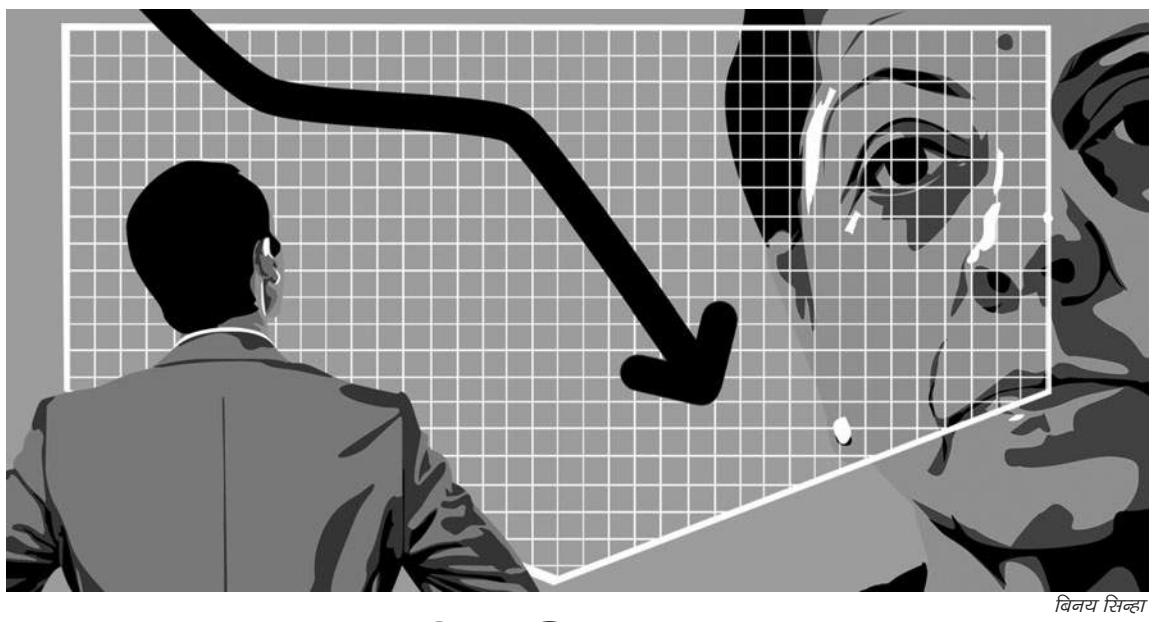

बिनय सिन्हा

बजट की विशेषताओं पर कुछ विचार

केंद्रीय बजट में चार उल्लेखनीय बातें शामिल रहीं। पहला संदर्भ, दूसरा पारदर्शिता, तीसरा विस्तारवाद और चौथा संरक्षणवाद। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी राय रख रहे हैं **शंकर आचार्य**

बजट प्रस्तुत हुए 15 दिन हो चुके हैं। इसके बारे में मीडिया में लगभग सबकुछ कहा जा चुका है। यही कारण है कि यहां मैं केवल चार विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगा।

बजट भाषण और उसका संदर्भ

तमाम बजट भाषण एक खास आर्थिक संदर्भ में तैयार किए जाते हैं। उनका प्रभाव और उनकी सफलता केवल बजट घोषणाओं की विषयवस्तु पर निर्भर नहीं करती है। बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि वित्त मंत्री उसे कितने विश्वसनीय तरीके से प्रस्तुत करते हैं और सरकार की उन आर्थिक और वित्तीय नीतियों को किस प्रकार रेखांकित करते हैं जो आने वाले वर्षों में आर्थिक विकास को कितने बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाते हैं। मौजूदा बजट के आर्थिक संदर्भों में बीते दो वर्ष की तीव्र आर्थिक मंदी, 50 वर्ष में सबसे खराब बेरोजगारी, निर्यात में सात वर्ष से ठहराव, निवेश दर में गिरावट, वित्तीय तंत्र में तनाव और विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त संकट आदि शामिल थे। दूसरे शब्दों में कहें तो आर्थिक हालात संकटपूर्ण हैं। बजट भाषण में निराश करने वाली बात यह थी कि शुरुआती पन्नों में इनमें से किसी का उल्लेख देखने को नहीं मिला। शायद मंत्री चाहती थीं कि नकारात्मकता न फैले। परंतु परिणाम क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे सरकार इसे नकार रही है। इससे भाषण का प्रभाव कम हुआ। बेहतर तरीका कुछ यूं होता: सबसे पहले, आर्थिक चुनौतियों की गंभीरता को चिह्नित किया जाता, उसके बाद सितंबर और अक्टूबर में बजट के पहले इस दिशा में उठाए गए कदमों का जिक्र होता जिसमें कॉर्पोरेट कर दरों में कमी जैसे कदम शामिल हैं, इसके बाद बताया जाता कि कैसे वित्त मंत्री के बजट प्रस्ताव पूरे रुझान में सुधार करेंगे, इसके बाद उन उपायों और प्रस्तावों का जिक्र किया जाता जो निवेश, वृद्धि, रोजगार और निर्यात में सुधार सुनिश्चित करेंगे।

बजट आंकड़े: पारदर्शिता और हकीकत

किसी भी बजट का बुनियादी उद्देश्य है बीते वर्ष का ईमानदार लेखाजोखा और आने वाले वर्ष के बारे में हकीकत के करीब अनुमान पेश करना। खेद की बात है कि देश में बजट प्रस्तुतीकरण में आंकड़ों की बाजीगरी आम हो चली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को यह श्रेय देना होगा कि इस बजट में उन्होंने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अहम उपाय किए और बजट से इतर व्यय/उधारी का वक्तव्य प्रस्तुत किया। इससे पता चलता है कि सन 2019-20 में जीडीपी का करीब 0.85 फीसदी हिस्सा ऐसे व्यय और उधारी पर खर्च हुआ या अगले वर्ष होगा। इसमें सरकारी बैंकों के पुनर्पूंजीकरण पर व्यय होने वाली राशि शामिल नहीं है। इसमें बड़ा हिस्सा एफसीआई के जरिये दी जाने वाली खाद्य सब्सिडी का है। यदि इसे दर्शाए गए राजकोषीय घाटे में शामिल किया जाए तो इन वर्षों का राजकोषीय घाटा क्रमश: 4.6 और 4.4 प्रतिशत हो जाएगा।

पारदर्शिता में इस सुधार का स्वागत है। परंतु प्रश्न यह है कि एनएचएआई और नाबार्ड के ऐसे ही लेनदेन को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया? यदि सरकारी कर्ज में जुड़ने वाली चीजों के लिए सही मानक का प्रयोग किया जाए तो एफडी प्रवाह को भी शामिल किया जाना चाहिए। सरकारी बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की राशि इससे बाहर क्यों है? इन्हें शामिल करने पर वर्ष 2015 के बाद के सभी वर्षों में एफडी अनुपात 5 फीसदी से ऊपर निकल जाएगा। अधिक बुनियादी बात करें तो चूंकि ये बढ़े हुए आंकड़े वास्तविक राजकोषीय घाटे के करीब हैं तो फिर 3.8 और 3.3 फीसदी के घटे हुए आंकड़े की जगह वास्तविक आंकड़े क्यों नहीं पेश किए गए? यह सुखद है कि 15वें वित्त आयोग की ताजा रिपोर्ट बजट से इतर उधारी और व्यय की सहायता लेने की स्पष्ट आलोचना और इन्हें समयबद्ध तरीके से बाहर करने की बात करती है। यह ऐसे विधिक ढांचे की भी बात करती है कि जहां हर सरकारी स्तर पर बजटिंग, अकाउंटिंग, आंतरिक नियंत्रण और अंकेक्षण मानकों का पालन किया जाए। यह भी जरूरी कदम है।

बजट: विस्तारवादी या संकुचनवादी

बजट में राजकोषीय प्रोत्साहन की अपर्याप्तता को लेकर काफी कुछ कहा जा चुका है। कुछ लोग इसे संकुचनवादी बता रहे हैं। यह बात मेरी समझ से परे है। केंद्र सरकार का बजट जिसमें जीडीपी के 5 फीसदी या उससे अधिक के एफडी की बात कही जा रही है वह संकुचनवादी कैसे हो सकता है? राज्यों में इसके तीन फीसदी हिस्से को शमिल करें तो कुल एफडी जीडीपी के 8 फीसदी के बराबर होगा। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की ऋण आवश्यकता जीडीपी के 9-10 फीसदी तक होगी। यदि विनिवेश प्राप्तियों को कमतर वर्गीकृत किया जाए तो बदलाव की दिशा विस्तारवादी अवश्य हो जाएगी क्योंकि आंकड़ा बढ़कर तीन गुना हो जाएगा।

यानी वित्त मंत्री की सराहना की जानी चाहिए कि उन्होंने प्रोत्साहन चाहने वालों को प्रसन्न करने के लिए उच्च एफडी योजना पेश नहीं की। ऐसा करना राजकोषीय घाटे, सरकारी ऋण और जीडीपी के 70 फीसदी के अनुपात और जीडीपी की कमजोर वृद्धि के मौजूदा दौर में सही नहीं होता।

संरक्षणवादी सीमा शुल्क और प्रक्रियाएं

इस बजट की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह लगातार संरक्षणवाद की ओर झुकता नजर आया। अरुण जेटली के फरवरी 2018 के बजट और पीयूष गोयल फरवरी 2019 के अंतरिम बजट सहित यह लगातार चौथा बजट है जहां तमाम वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाया गया है। इस वर्ष विभिन्न घरेलू वस्तुओं और उपकरणों, इलेक्ट्रिकल उपकरणों, जूते-चप्पल, फर्नीचर, खिलौने, मशीनरी, चिकित्सा उपकरणों, मोबाइल फोन घटकों, ई-वाहनों और बादाम आदि पर शुल्क बढ़ाया गया। ऐंटी डंपिंग शुल्क और सेफ-गार्ड शुल्क दरों को भी बढ़ाया जा रहा है। कुल मिलाकर आयात की राह और मुश्किल हो रही है।

सन 1991 के बाद से 25 वर्ष की अवधि में विभिन्न भारतीय सरकारों ने व्यापार नीतियों में सुधार किया और विश्व व्यापार के साथ संबद्धता बढ़ाई और खुलापन लाया। सीमा शुल्क में कमी की गई और इसकी बाधाओं को कम किया गया। परिणामस्वरूप, हमारा विदेशी व्यापार बढ़ा। इससे हमारी आर्थिक वृद्धि और रोजगार दोनों बेहतर हुए। वर्ष 2017 के बाद से हमने नीति को पलटना शुरू कर दिया और विश्व व्यापार से अपने संबंध कम किए। हमारे मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी यह मानने को तैयार नहीं दिखते कि उच्च शुल्क और आयात प्रतिबंध हमारी निर्यात क्षमता को प्रभावित कर रहे हैं। किसी बड़े गैर तेल निर्यातक देश ने आयात को बाधित करके निर्यात वृद्धि हासिल नहीं की है। न ही ऐसा कोई देश बिना उच्च निर्यात वृद्धि के सकल आर्थिक वृद्धि हासिल कर पाया है। सन 1992 से 1997 और 2003 से 2012 के बीच जब हमारा निर्यात मजबूत था तब हमारी अर्थव्यवस्था भी तेजी से विकसित हुई।

यदि हम अपने ही आर्थिक इतिहास से सबक नहीं लेंगे तो देश की धीमी आर्थिक प्रगति के लिए किसी और को दोष नहीं दे सकते।

(लेखक इक्रियर में मानद प्रोफेसर और भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ऑनलाइन कंटेंट कारोबार पर क्यों है सबकी नजर ?

मीडिया मंत्र

वनिता कोहली-खांडेकर

दूरसंचार, टेक्नॉलजी, मीडिया और यहां तक कि खुदरा कारोबार कंपनियां तक सभी को दर्शकों की तलाश है। इस दौरान कई छंट जाएंगे। कोई सफल होगा या नहीं, इसकी पहचान करने के लिए यह जांचना होगा कि उनके कारोबार में उपभोक्ता से प्रत्यक्ष संपर्क का तत्त्व है या नहीं।

यह अजीब मौसम है। समाचार प्रस्तोता और राजनेता एक पूरे शहर को राष्ट्र विरोधी घोषित कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनकी पसंद के एक खास दल को वोट नहीं दिया। उम्रदराज पुरुष और स्त्रियां नफरत की वकालत कर रहे हैं जबकि खुद उनके बच्चे उन्हें शांति और विविधता के फायदे समझा रहे हैं। देश के 1,67,400 करोड़ रुपये वाले मीडिया और मनोरंजन उद्योग का यही योगदान है।

समाचार प्रकाशकों से लेकर मनोरंजन कंपनियों तक, फूड एग्रीगेटर से लेकर ई-कॉमर्स जगत की कंपनियों तक सभी 'कंटेंट फर्म' बनना चाहते हैं। यानी ऐसी फर्म जो दृश्य-श्रव्य माध्यम में सामग्री प्रस्तुत करे। इनमें सबसे नया नाम है 635 करोड़ रुपये मूल्य की एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया (ईएनआईएल)। यह 10,000 करोड़ रुपये मूल्य वाले टाइम्स समूह का हिस्सा है। ईएनआईएल देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क रेडियो मिर्ची का संचालन करती है और उसके राजस्व का 67 फीसदी रेडियो से आता है। जबकि आने वाले कुछ सप्ताह में कंपनी का रेडियो से संबंध नहीं रह जाएगा। कंपनी ने अन्य ब्रांडों के बीच अपने सहोदर मैक्स प्लेयर के लिए 25 घंटे की सामग्री तैयार की है। इस सामग्री में गुजराती और तमिल समेत विभिन्न भारतीय भाषाओं में 10-10 मिनट की सामग्री तैयार की गई है। सन 2024 तक मिर्ची अपने राजस्व का आधा हिस्सा गैर रेडियो कारोबार से हासिल करने की आशा कर रही है। इसमें 'कंटेंट' बेचना भी शामिल है।

10 वर्ष से अधिक समय से मैंने सुना है कि कैसे दुनिया भर की मीडिया फर्म 'कंटेंट फर्म' बनने की बात करती हैं। परंतु अब इसकी गति बहुत तेज हो गई है। ऐसा क्यों हो रहा है, यह समझने के लिए हमें अतीत की गलियों से गुजरना होगा।

सन 1990 के दशक के आखिर से लेकर नई सहस्राब्दी के शुरुआती समय तक इंटरनेट ने पहले संगीत, फिर समाचार पत्रों, टेलीविजन और फिल्म कारोबार पर जो दबाव डाला, इसका अर्थ माध्यम को लेकर इन सभी के मन में संशय के रूप में उभरा। उदाहरण के लिए समाचार पत्र कंपनियां वर्षों तक खुद को 'कंटेंट फर्म' बताती रहीं। जबकि उनके मुनाफे का ज्यादातर हिस्सा सामान्य मुद्रित उत्पाद से आता रहा। 'कंटेंट' पर्याप्त शोध से हासिल होता है जिसे प्रकाशित करके श्रोताओं को प्रभावित किया जाता है और फिर तमाम माध्यमों से राजस्व जुटाया जाता है। खुद को 'कंटेंट फर्म' कहकर इनमें से अधिकांश स्वयं को मुद्रित माध्यम के इर्दगिर्द मौजूद नकारात्मक रुझान से बचा रही थीं। पश्चिमी दुनिया में मुद्रित माध्यम सिमट रहा है। यही कारण है कि टेलीविजन और फिल्म कंपनियों ने ऐसा किया। वृद्धि के पारंपरिक दायरे में लगभग सभी मीडिया कंपनियों ने तीन-चार अलग-अलग कारोबारी क्षेत्रों में प्रयास किया। समाचार पत्र रेडियो, स्थानीय टेलीविजन स्टेशनों और इंटरनेट की ओर बढ़े। टेलीविजन कंपनियों ने कंटेंट उत्पादन, डीटीएच या केबल का रुख किया। इसे विविधता कहा गया। ईएनआईएल या डिज्नी या सोनी यही कर रहे हैं। उदाहरण के लिए ईएनआईएल के पास देश के 63 शहरों में 1,100 कर्मचारी हैं और यह आपके यूट्यूब चैनल और कार्यक्रमों के लिए विज्ञापन बेचना, कंटेंट तैयार करना चाहती है।

बहरहाल विविधता कोई फैशन में इस्तेमाल होने वाला शब्द नहीं है। प्रश्न यह है कि कोई कंपनी यह कैसे बताती है कि वह वृद्धि और भविष्योन्मुखी है। दरअसल तब हर चीज कंटेंट हो जाती है- एक टेलीविजन शो, एक फिल्म, संगीत का कोई हिस्सा, एक निबंध, एक किताब या आलेख, वीडियोज, हेयरस्टाइल टिप्स या रोटी बनाने की कला आदि कुछ भी। कंटेंट शब्द फिल्म देखने या संगीत सुनने के जादू को समाप्त कर देता है लेकिन इसका अर्थ एकदम स्पष्ट है। यह दर्शकों तथा श्रोताओं को जोड़े रखने का काम करता है।

इस बात से समझा जा सकता है कि मीडिया और मीडिया से बाहर की कंपनियां कंटेंट का रुख क्यों कर रही हैं। उनकी वजहों को समझकर ही उनमें भेद किया जा सकता है।

जोमैटो या फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां चाहती हैं कि लोग उनकी सेवाओं पर अधिक से अधिक समय और पैसा खर्च करें। गूगल, डिज्नी, वायकॉम 18 या जी जो टेलीविजन पर करती हैं, वही वे एक अन्य माध्यम पर कर रही हैं। ईएनआईएल (तथा अनेक अन्य रेडियो फर्म) रेडियो की प्रासंगिकता की लड़ाई लड़ रही हैं, वह भी एक ऐसे बाजार में जहां ढेर सारे नए फोन में एफएम सुविधा नहीं है।

अन्यान्य वजहों से दूरसंचार, टेक्नॉलजी, मीडिया और यहां तक कि खुदरा कारोबार कंपनियां तक सभी को दर्शकों की तलाश है।

इस दौरान कई छंट जाएंगे। कोई सफल होगा या नहीं, इसकी पहचान करने के लिए यह जांचना होगा कि उनके कारोबार में उपभोक्ता से प्रत्यक्ष संपर्क का तत्त्व है या नहीं। टेलीविजन कंपनियां जहां अपने सिग्नल केबल और डीटीएच ऑपरेटरों को बेचती हैं और विज्ञापनदाताओं की मदद से आय अर्जित करती हैं, उनके उलट फिल्म स्टूडियो को सीधे दर्शक जुटाने होते हैं और उनसे ही पैसे खर्च कराने होते हैं। किस्से कहने की उनकी क्षमता बेहतर है। ध्यान दीजिए तो पाएंगे कि कई स्ट्रीमिंग सेवाओं का शुरुआती बेहतर कंटेंट फिल्म स्टूडियोज से आता है।

बदलाव अभी शुरू हुआ है। अभी कुछ अरसे तक मौजूदा मूर्खतापूर्ण दौर चलता रहेगा।

कानाफूसी

सदन में विरोध

उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन प्याज, आलू और तमाम चीजें देखने को मिलीं। गुरुवार को शुरू हुए सत्र के पहले दिन विपक्षी दलों के विधायकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यह कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ था। कुछ विधायकों ने हाल ही में घरेलू गैस की कीमतों में किए गए इजाफे का भी विरोध किया। जैसे ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने भाषण की शुरुआत की, लाल टोपी पहने समाजवादी पार्टी के विधायक विरोध के लिए सदन के बीच में पहुंचने लगे। कुछ वहीं फर्श पर बैठ गए। कुछ विधायकों ने हाथ में तख्तियां थाम रखी थीं जिन पर नागरिकता संशोधन अधिनियम और संभावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी की आलोचना की गई थी। इस दौरान अफरातफरी मची रही और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ असहाय देखते रहे।

बदलाव की बात

दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए चार दिन बीत चुके हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी में आरोप-प्रत्यारोप का दौर अब भी जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सुझाव दिया है कि पार्टी अप्रासंगिक हो रही है और उसे नए सिरे से अपनी तलाश करनी होगी। वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने भी पार्टी में नई जान फूंकने के लिए 'सर्जिकल' कदम उठाने की आवश्यकता जताई। कांग्रेस पार्टी का पूर्ण अधिवेशन अप्रैल में होने वाला है। माना जा रहा है कि उसी दौरान राहुल गांधी को दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाएगा। संभव है उस दौरान सोनिया गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इस बात से अवगत कराएं कि उनकी सेहत अब ऐसी नहीं है कि वह अंतरिम अध्यक्ष का पद संभाल सकें।

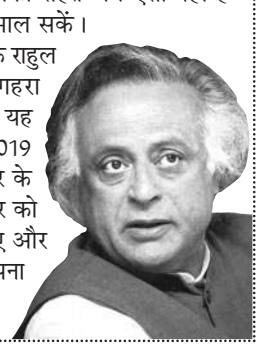

हालांकि वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि राहुल की वापसी से पार्टी का संकट और गहरा हो जाएगा। आने वाले सप्ताहों में उन्हें यह याद दिलाया जा सकता है कि उन्होंने 2019 में लोक सभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद सुझाव दिया था कि गांधी परिवार को पार्टी अध्यक्ष पद से दूर रहना चाहिए और कांग्रेस को किसी बाहरी नेता को अपना अध्यक्ष बनाना चाहिए।

आपका पक्ष

नमामि गंगे से जुड़ें सभी लोग

गंगा देश की पवित्र एवं सबसे लंबी नदी ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म के लोग इसे पवित्र मानते हैं। आज गंगा के साथ इतना अन्याय होने के बाद भी वह अनवरत बह रही है। हिमालय में ग्लेशियर से जलधारा मिलती है और ऋषिकेश, हरिद्वार में आने पर वृक्ष वनस्पतियों की हरी चादर इसे भरा पूरा बनाती है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियर पिघल रहे हैं। वृक्ष, वनस्पतियों के कटने के कारण भूक्षरण हो रहा है। गंगा को साफ करना भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती गंगा में प्रवाहित किए जाने वाले गंदा पानी को रोकना है। इस नदी के जल में ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखने की असाधारण क्षमता है। लेकिन गंगा के तट पर बसे औद्योगिक नगरों के नालों की गंदगी सीधे गंगा में मिलने

से गंगा का प्रदूषण पिछले कई वर्षों से चिंता का विषय बना हुआ है। औद्योगिक कचरे के साथ-साथ प्लास्टिक कचरे ने भी गंगा को प्रदूषित किया है। सरकार ने गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नमामि गंगे योजना शुरू की है। इस योजना के तहत गंगा नदी को 2020

गंगा नदी को साफ करने में सरकार के साथ लोगों की भागीदारी भी जरूरी है

तक प्रदूषण मुक्त करने का संकल्प लिया गया है। लेकिन हाल की स्थिति को देख कर लक्ष्य पूरा होता नहीं दिख रहा है। गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसकी सफलता के लिए जरूरी है कि सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं, वाणिज्यिक उपक्रम और धार्मिक संस्थान भी पूरी ईमानदारी के साथ इस राष्ट्रीय कार्यक्रम से जुड़ें। गंगा के आस-पास रहने वाले प्रत्येक लोगों का भी यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि वह इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में अपना सकारात्मक योगदान करे।

अनु मिश्रा, सीवान

नेतागण अमर्यादित बयानबाजी से बचें

हर राजनीतिक पार्टी के नेताओं को अपने बयान मर्यादा में रहकर देना चाहिए। समय-समय पर विभिन्न दलों के नेताओं की अमर्यादित बयानबाजी सामने आती रही है। चुनाव के समय कुछ नेता अभद्र भाषा का प्रयोग कर आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। जो नेता अमर्यादित बयानबाजी करते हैं उन्हें एक बात याद रखनी चाहिए कि जबान से समाज में इज्जत बढ़ती है और जबान से इंसान की इज्जत मिट्टी में मिलते देर नहीं लगती है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र देश के नेताओं को अभद्र बातें शोभा नहीं देती हैं। उन्हें खुद ही इन पर लगाम लगानी चाहिए। चुनाव आयोग को भी चाहिए कि वह अभद्र बातें करने वालों नेताओं पर लगाम कसने के लिए उचित कदम उठाए, ताकि हमारे देश की राजनीति की बड़बोले नेताओं के कारण बिगड़ती छवि को सुधारा जा सके।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

संक्षेप में

कृषि उत्पाद बढ़ाना जरूरीः उपराष्ट्रपति

आबादी की समस्या और कृषि उत्पादन बढ़ाना न सिर्फ हमारी खाद्य सुरक्षा, बल्कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। अगर आबादी इसी तरह से बढ़ती रही और आपने इसी हिसाब से उपज में वृद्धि नहीं की, तो आने वाले समय में समस्या उत्पन्न होगी। यह बात उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 58वें दीक्षांत समारोह में कही। उन्होंने कहा कि वैश्विक भूख सूचकांक की सूची में भारत का निम्न श्रेणी में होना चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि नीति निर्माताओं और कृषि वैज्ञानिकों को आत्मचिंतन करना चाहिए तथा देश में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए इस मुद्दे का हल निकालना चाहिए। नायडू ने कहा, 'देश का खाद्यान्न उत्पादन 2,833.7 लाख टन है और इस हिसाब से भारत अच्छी स्थिति में है। हालांकि भारत वैश्विक भूख सूचकांक में 102वें स्थान पर है। यह चिंता का विषय है।' उन्होंने कहा, नीति निर्माताओं, राजनेताओं, सांसदों, कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि वैज्ञानिकों को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए कि हम अब भी वैश्विक भूख सूचकांक में 102वें स्थान पर क्यों हैं। *भाषा*

वियतनाम को भारतीय बाजार से उम्मीद

चीन के साथ अपने व्यापार पर कोरोनावायरस के असर को कम करने के लिए वियतनाम अपना कृषि उत्पाद निर्यात भारत में बढ़ाने पर विचार कर रहा है। चीन उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। वियतनाम ने भारत से कहा है कि वह काली मिर्च और काजू जैसी जिंसों के उसके निर्यात पर व्यापारिक रुकावट कम करे। उद्योग और व्यापार मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वियतनाम और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार में खासे इजाफे की गुंजाइश है। दोनों देशों ने पिछले साल का 11.3 अरब डॉलर का कारोबार बढ़ाकर 15 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वियतनाम के उप व्यापार मंत्री काओ कुओक हुंग के भारत दौरे के बीच यह बयान आया है। वे द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने और चीन में वायरस के प्रकोप के कारण वियतनाम के कृषि उत्पाद निर्यात को होने वाली दिक्कतों के उपयों पर चर्चा के लिए भारत के दौरे पर हैं। *रॉयटर्स*

वैश्विक खाद्य तेल व्यापार में हलचल

मलेशिया से पाम तेल आयात पर रोक से वैश्विक स्तर पर पड़ रहा असर

रॉयटर्स
कुआलालम्पुर /मुंबई, 14 फरवरी

तेल आयात

- पिछले साल के मुकाबले जनवरी में भारत का पाम तेल आयात 27 प्रतिशत फिसलकर 5,94,804 टन रहा
- सोया तेल और सूरजमुखी तेल का आयात बढ़कर 40 और 51 प्रतिशत हो गया
- इससे देश की खाद्य तेल आयात बास्केट में पाम तेल की हिस्सेदार पर दबाव बना और यह हिस्सेदारी कम होकर 51 प्रतिशत रह गई
- जून 2018 के बाद से सबसे निचला स्तर है

भारत द्वारा मलेशिया के पाम तेल आयात पर रोक से वैश्विक खाद्य तेल कारोबार प्रभावित हुआ है। भारत की मांग पूरी करने के लिए इंडोनेशिया ने अपनी आपूर्ति का रुख उसकी ओर कर दिया है। इससे मलेशिया इंडोनेशिया द्वारा छोड़े गए बाजारों में पहुंच बनाने की होड़ में लग गया है और भारत पाम के बदले अन्य तेलों का विकल्प चुन रहा है।

दुनिया के शीर्ष पाम तेल खरीदार भारत ने पिछले महीने रिफाइंड पाम तेल आयात पर प्रतिबंध लगा दिए थे। सूत्रों का कहना है कि भारत के नए नागरिकता कानून और कश्मीर की कार्रवाई पर मलेशिया द्वारा की गई आलोचना के जवाब में यह कदम उठाया गया था। कारोबारियों ने भी मलेशिया से कच्चे पाम तेल की खरीद रोक दी थी।

मलेशिया के पाम निर्यात के नवीनतम आंकड़ों से भारत के प्रतिबंधों के असर का पता चलता है। जनवरी में भारत को भेजी गई खेपें पिछले साल की तुलना में 85 प्रतिशत लुढ़ककर 46,876 टन रह गई। वर्ष 2011 के बाद से यह सबसे कम स्तर है। पिछले साल मलेशिया के कुल पाम तेल निर्यात में भारत का योगदान करीब एक-चौथाई रहा था और यह पांच साल से मलेशिया के पाम तेल का सबसे बड़ा खरीदार रहा है।

इसकी भरपाई के लिए मलेशिया ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और घाना को निर्यात करने के साथ ही अपनी खेपें का रुख अन्य गंतव्य देशों की ओर कर दिया है। ये वे बाजार हैं जो परंपरागत रूप से इंडोनेशिया से बड़ी मात्रा में खरीदारी करते रहे हैं।

वैश्विक स्तर पर व्यापार करने वाली एक कंपनी के मुंबई स्थित कारोबारी ने कहा कि पाम तेल बाजार में फिर से संतुलन स्थापित हो रहा है। यूरोपीय और दामों के प्रति संवेदनशील रहने वाले एशिया के खरीदार कम दामों के कारण इंडोनेशिया से मलेशिया की ओर जा रहे हैं। भारत द्वारा अधिक खरीद की उम्मीद से इस साल इंडोनेशिया के दाम बढ़कर मलेशिया के स्तर पर चले गए हैं।

सरकारी एजेंसी और उद्योग के संगठन मलेशिया पाम तेल परिषद (एमपीओसी) के अध्यक्ष ली येओउ चॉर ने कहा कि मलेशिया में भंडार के कम स्तर के कारण अब तक उत्पादकों को सहारा मिलता रहा है। अन्यथा भारत के हटने से पड़ने वाला असर ज्यादा गंभीर होता।

ली ने कहा, 'फिलहाल मलेशिया के लिए स्थिति गंभीर नही है। अब भी हमारा स्टॉक कम है ... (भारत) इंडोनेशिया से और खरीद कर सकता है। लेकिन इससे बाजार में कहीं न कहीं कोई जगह बनेगी।' मलेशिया का भंडार दो साल के निचले स्तर पर है।

ली ने कहा कि मलेशिया पूर्वी एशिया, दक्षिण-पूर्वी एशिया और अफ्रीका में बाजार हिस्सेदारी का विस्तार करने पर विचार कर रहा है। मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले महीने मलेशिया ने पाकिस्तान को 1,70,802 टन पाम तेल बेचा था, जबकि एक साल पहले 80,660 टन तेल बेचा गया था। मलेशिया ने बांग्लादेश को 12,527 टन तेल बेचा है जो पिछले साल के 575 टन की तुलना में अधिक है। पिछले साल इंडोनेशिया इन बाजारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था।

पाम तेल के विकल्प चुन रहा भारत

पिछले साल जुलाई से दिसंबर के दौरान बेंचमार्क पाम तेल के दामों में 60 प्रतिशत तक इजाफा हुआ है, अलबत्ता हाल ही में भारतीय मांग और चीन में कोरोनोवायरस के प्रकोप की चिंताओं से दामों में गिरावट आई है। दामों के प्रति संवेदनशील रहने वाले भारत ने बढ़ते दामों की वजह से पिछले तीन महीने में पाम की खरीद कम कर दी थी। पाम और अन्य तेलों की कीमतों के बीच घटते अंतर से भी पाम तेल के विकल्प चुनने को प्रोत्साहन मिला है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल के मुकाबले जनवरी में भारत का पाम तेल आयात 27 प्रतिशत फिसलकर 5,94,804 टन रह गया है, जबकि सोया तेल और सूरजमुखी तेल का आयात बढ़कर क्रमशः 40 और 51 प्रतिशत हो गया है। इससे देश की खाद्य तेल आयात बास्केट में पाम तेल की हिस्सेदार पर दबाव बना है और यह हिस्सेदारी कम होकर 51 प्रतिशत रह गई है जो जून 2018 के बाद से सबसे निचला स्तर है।

एसईए के कार्यकारी निदेशक बीवी मेहता ने कहा कि खरीदारों को बनाए रखने के लिए इंडोनेशिया के आपूर्तिकर्ता दाम कम कर सकते हैं वरना भारत वैकल्पिक तेलों की ज्यादा खरीद जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया मलेशिया की आपूर्ति के मुकाबले ज्यादा पैसा वसूली जारी नहीं रख सकता है। जब भी पाम तेल और मृदु तेलों के बीच का अंतर कम होता है, भारतीय खरीदार मृदु तेलों की ओर रुख कर लेते हैं।

उद्योग संगठन आईपीजीए ने कहा

दलहन आयात में आएगी 60 प्रतिशत तक गिरावट!

एजेंसियां
मुंबई, 14 फरवरी

- फसल वर्ष 2018-19 में 2.34 करोड़ टन तक घरेलू दलहन उत्पादन के बीच स्थानीय किसानों को संरक्षित करने के लिए सरकार ने मुख्य दालों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगा रखा है
- भारत दलहनों का दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है

उद्योग संगठन आईपीजीए ने आज कहा कि दलहन के आयात पर मौजूदा रोक जारी रही तो भारत का दलहन आयात वर्ष 2020-21 में 60 प्रतिशत घटकर 10 टन रह सकता है। इस गिरावट में घरेलू फसल के बेहतर रहने की संभावना और भारी मात्रा में उपलब्ध बफर स्टॉक का भी योगदान होगा।

भारतीय दलहन एवं अनाज संघ (आईजीपीए) के अध्यक्ष जीतू भेडा ने बताया कि अगले साल भी आयात कम होगा क्योंकि संभवतः व्यापारी आयात कोटा आदेश में खामियों का फायदा उठाकर आयात करने में सफल न हो पाएं क्योंकि सरकार इस कमजोरी को दूर कर रही है। आयात कोटा आदेश को कड़ा करने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) जयपुर उच्च न्यायालय में मुकदमा लड़ रहा है।

भेडा ने दलहन सम्मेलन 2020 के मौके पर कहा, 'चालू वर्ष में कुल दलहन आयात 25 लाख टन होने की उम्मीद है, जिसमें से लगभग 15 लाख टन का आयात किया जा चुका है। ऐसा डीजीएफटी के कोटे के आदेश पर चेन्नई और जयपुर उच्च न्यायालयों के स्थगन आदेश का लाभ उठा कर व्यापारियों द्वारा आयात बढ़ाने से संभव हो सका है। आयातित खेप में ज्यादातर पीली मटर, उड़द और हरी मटर शामिल है।' बाकी दस लाख टन कोटे के अनुरूप आयात किया गया है।

फसल वर्ष 2018-19 (जुलाई-जून) में 2.34 करोड़ टन तक घरेलू दलहन उत्पादन के बीच स्थानीय किसानों को संरक्षित करने के लिए सरकार ने मुख्य दालों, विशेष रूप से पीले मटर, तुअर (अरहर), छोले (काबुली चना) और मूंग के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगा रखा है। राजमा और लोबिया को बगैर किसी रोक-टोक के आयात करने की अनुमति है। भारत दलहनों का दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है।

प्रोटीन युक्त दालों के दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता देश भारत द्वारा आयात कम करने से घरेलू दामों को तो मदद मिलेगी, लेकिन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार और रूस में किसान समुदायों पर इसका असर होगा। भेडा ने उद्योग के दलहन सम्मेलन से इतर कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 में मार्च तक भारत का दलहन आयात कई गुना बढ़कर 25 लाख टन रहने की संभावना है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 2016-17 में रिकॉर्ड दलहन आयात से घरेलू दाम लुढ़क गए थे, भारत ने पीली मटर, हरे चने और काबुली चने जैसी किस्मों के लिए आयात कोटा लागू किया था। सरकार के इस कोटे के अनुसार कारोबारी केवल दस लाख टन दलहन का ही आयात कर सकते थे, लेकिन कारोबारियों ने विभिन्न अदालतों में याचिका दायर करके अतिरिक्त 15 लाख टन का आयात किया था।

देश के कुल दलहन आयात में लगभग आधा योगदान पीली मटर का रहता है। इस साल घरेलू काबुली चने का उत्पादन पिछले साल के 1.013 करोड़ टन से अधिक रहने का अनुमान है। इससे आयात से बचने में मदद मिलेगी। फिलहाल काबुली चने का भाव प्रति क्विंटल लगभग 4,000 रुपये चल रहा है जो सरकार द्वारा निर्धारित 4,875 रुपये के मूल्य से काफी कम हैं।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Feb 14	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,701.5	-3.1	1,975.6	3.8
Copper	5,716.0	-2.0	6,319.2	2.9
Nickel	13,065.0	-14.9	13,731.3	-15.2
Lead	1,877.0	-7.2	2,087.7	-1.8
Tin	16,530.0	2.1	17,444.3	2.5
Zinc	2,157.0	-12.2	2,396.0	-12.5
Gold ($/ounce)	1,576.2*	7.1	1,770.1	7.1
Silver ($/ounce)	17.7*	3.9	20.0	3.4
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	57.0*	-9.5	53.2	-15.2
Natural Gas ($/mmBtu)	1.8*	-30.9	1.9	-30.6
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	195.5	5.4	290.7	-2.6
Maize	183.0*	1.2	253.5	-4.5
Sugar	417.7*	26.0	486.5	0.4
Palm oil	680.0	7.1	1,110.8	10.3
Rubber	1,448.5*	-3.6	1,933.6	7.9
Coffee Robusta	1,272.0*	-8.1	1,807.5	-3.3
Cotton	1,491.2	5.2	1,574.2	0.2

* As on Feb 14, 20 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.4& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel. 3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	45.4	39467
Oil and Oilseeds	218.3	86228
Spices	1.1	9
Metal(Feb 13)		
Metal- non ferrous	5857.3	50476
Metal- precious	8840.0	405
Oil and gas(Feb 13)		
Gas	2420.0	50745
Oil	17870.1	2435

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	112.0	128922
Grains	121.0	88585
Oil and Oilseeds	658.5	409000
Others	89.0	62820
Pulses	94.3	46485
Spices	73.9	21186\

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Zinc (May 29)	173.2	1.9
Lead Mini (Feb 28)	147.5	1.1
Zinc Mini (Feb 28)	169.7	1.0
Nickel (Feb 28)	961.3	0.8
Natural Gas (Feb 25)	132.0	0.8
Silver Mini (Feb 28)	45821.0	0.7
Silver (Mar 05)	45799.0	0.7
Silver Micro (Feb 28)	45828.0	0.7
Losers (* % Change)		
Cardamom (Mar 13)	3273.4	-3.5
Mentha Oil (Feb 28)	1139.2	-1.2
Cotton (Feb 28)	19010.0	-0.4
Kapas (Apr 30)	1050.5	-0.3

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Losers (* % Change)		
Jeera Unjha (Mar 20)	13990.0	3.0
Soyabean Indore (Feb 20)	4044.0	1.8
CastorSeed New-Disa (Feb 20)	3926.0	1.8
Coriander-Kota (Apr 20)	6259.0	0.9
Chana-Bikaner (Mar 20)	4042.0	0.6
CottonSeed Oil-Akola (Feb 20)	1790.0	0.6
GuarGum 5T-Jodhpur (Feb 20)	6673.0	0.4
Losers (* % Change)		
Bajra (Feb 20)	1858.0	-3.0
Maize IndusNizamabad (May 20)	1715.0	-2.2
Mustard Seed Rape Oil (Feb 20)	3983.0	-1.8
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1050.5	-0.4
Barley Jaipur (Apr 20)	1695.0	-0.4

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Kapas Surendranagar (Apr 30)	1050.5	3.8
Cotton-Rajkot (Feb 28)	19010.0	0.8
Zinc Mumbai (May 29)	173.2	0.6
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Feb 28)	1139.2	-11.3
Cardamom Vandanmedu (Mar 13)	3273.4	-11.1
Lead Min Mumbai (Feb 28)	147.5	-1.8
Gold Petal-Mumbai (Feb 28)	4014.0	-1.5
Zinc Mini Mumbai (Feb 28)	169.7	-1.4
Nickel Mumbai (Feb 28)	961.3	-0.6
Alumini-Mumbai (Feb 28)	139.2	-0.6
Aluminium Mum (May 29)	139.5	-0.4
Lead Mum (May 29)	149.6	-0.4

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Bajra-Jaipur (Feb 20)	1858.0	4.0
Bajra-Delhi (Feb 20)	1858.0	1.5
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	5850.0	0.9
Maize-Sangli (Feb 20)	1803.0	0.6
29 mm Cotton-Rajkot (Feb 20)	18820.0	0.1
Discount over spot price (In %)		
Barley Jaipur (Apr 20)	1695.0	-20.4
Jeera Unjha (Mar 20)	13990.0	-2.0
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Feb 20)	6673.0	-1.9
Crude Palm Oil Kandl (Feb 28)	729.2	-1.4
Soy Bean Indore (Feb 20)	4044.0	-1.3
Moong-Merta City (Feb 20)	7642.0	-1.0

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals	...Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg	105...(105)
Aluminium ingots /kg	141...(141)
Brass sheet cutting /kg	325...(328)
Brass utensil scraps/kg	310...(311)
Copper heavy scrap /kg	418...(418)
Copper utensil scraps/kg	394...(394)
Copper wire bar /kg	451...(451)
Lead ingots /kg	149...(149)
Nickel Cathodes /kg	980...(980)
Tin slabs /kg	1245...(1245)
Zinc slabs /kg	171...(171)

Source:Bombay Metal Exchange

Cotton	...Mumbai
Bengal Deshi /Qtl	10151...(10151)
DCH - 32 /Qtl	11304...(11332)
Jaydhar /Qtl	9758...(9758)
Shankar- 6 /Qtl	11051...(11079)

Source:Cotton Association of India

Oil	...Mumbai
Castor FSG /10kg	845...(835)
Castor Comm /10kg	835...(825)
Ricebran oil/10kg	-...(820)
Groundnut oil /10kg	1140...(1140)
Linseed oil /10kg	...-(900)
Karanji /10kg	-...(800)
Palm oil /10kg	810...(830)
Sunflower exp ref /10kg	870...(875)
Sunflower oil exp /10kg	810...(820)
Soyabean ref / 10kg	830...(842)

Source:Bombay Commodity Exchange

सॉफ्ट

Sugar	...Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl	3352-3592 ...(3356-3602)

Source:Bombay Sugar Merchants Association

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel	...
NYSE Crude	51.92...(51.42)
Brent Crude (UK)	57...(56.38)
Brent Crude (WTI)	51.42...(51.42)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu	1.8...(1.83)
Furnace/ 180 Cst &/bbl	304.31 ...(302.32)
Naptha spot /Rs/MT	45170...(45170)
LSHS spot/ M.T.	36150...(36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	33950...(33950)

Source:Petroleum Bazaar.com

सर्राफा

Gold	...Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms	40617...(40603)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	40780...(40766)
Silver.999/ kg	46000...(45890)

Source:India Bullion & Jewellers Association

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	18794.40	18795.30
Alumini-Mumbai (M)	1 K	140.15	140.00
Bajra-Delhi (N)	1 Q	1830.00	1830.00
Bajra-Jaipur (N)	1 Q	1797.50	1787.10
Barley Jaipur (N)	1 Q	2134.05	2130.30
Cardamom-Vand. (I)	1 K	3733.00	3667.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4000.00	4026.95
Castor Seed-Kadi (N)	X	3987.50	4025.00
Chana Bikaner (N)	1 Q	4077.50	4078.35
Chana Delhi (N)	1 Q	4300.00	4300.00
Chana-Akola (N)	X	4087.50	4050.00
Coriander-Gondal (N)	X	6171.00	6040.00
Coriander-Jaipur (N)	X	6202.20	6221.25
Coriander-Kota (N)	1 Q	6335.00	6255.95
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	1864.75	1856.65
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	1904.15	1902.25
Cotton-Kadi (N)	1 B	18883.60	18883.60
CPO-Kandla (M)	10 K	741.90	739.00
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	740.55	739.35
Crude Palm Oil-KAKIN (N)	10 K	720.00	715.00
Diamond 0.3 - Surat (I)	1 CT	905.95	904.25
Diamond 0.5-Surat (I)	1 CT	1553.65	1550.85
Diamond 1-Surat (I)	1 CT	3462.55	3455.95
Gold Ahm (M)	10 G	40619.00	40676.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	32626.00	32672.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	4076.00	4075.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	6891.65	6800.00
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	3884.40	3850.00
Guarseed-Jodhpur (I)	1 Q	3850.00	3793.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1095.95	1099.35
Isabgulseed-Unjha (I)	1 K	103.00	102.85
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	14950.00	15000.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	14372.00	14271.45
Kachi Ghani Must Oil (N)	10 K	825.65	820.00
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1015.60	1015.60
Kapas-Rajkot (N)	X	1007.30	1007.30
Lead Mum (M)	1 K	152.00	150.10
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	1860.00	1825.00
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2041.50	2031.25
Maize-Erode (N)	X	1874.45	1900.00
Maize-Feed/Ind- Gula (N)	1 Q	2041.50	2031.25
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	1950.00	1912.50
Maize-Sangli (N)	X	1800.20	1791.65
Masoor Grain Bold In (N)	1 Q	4750.00	4750.00
Moong-Merta City (N)	1 Q	7633.35	7720.00
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4256.75	4231.00
Nickel Mumbai (M)	1 K	966.40	967.10
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3100.00	3100.00
Paddy-Basmati-Karnal (I)	1 Q	3136.00	3124.00
Pepper-Ernakulam (I)	1 K	334.40	335.00
Pepper-Kochi (N)	1 Q	33372.75	33766.65
R M Oil-Sriganganaga (N)	X	820.00	822.50
Rape mustards-Patan (I)	20 K	758.00	761.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	1895.00	1900.00
Raw Jute-Kolkatta (N)	X	5366.65	5366.65
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	796.65	792.80
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	850.50	847.85
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	845.00	838.90
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	850.00	848.00
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13800.00	13800.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)	1 Q	13767.00	13725.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	45842.00	45928.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4094.00	4096.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	4008.45	4002.15
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4191.50	4191.50
Soy Bean-Akola (N)	X	4040.00	4070.00
Soymeal Indore (N)	1 T	32700.00	32800.00
Soyoil-Indore (I)	10 K	850.80	848.00
Steel Long-Ghaziabad (I)	1 T	30630.00	30710.00
Steel Long-MGG (I)	1 T	31000.00	31200.00
Steel Long-Raipur (I)	1 T	28430.00	28500.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3217.50	3235.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3366.65	3329.40
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3275.65	3292.00
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3442.85	3428.55
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3250.00	3278.55
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3151.25	3152.50
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	5805.70	5800.00
Wheat Delhi (N)	1 Q	2200.00	2200.00
Wheat Kota (N)	1 Q	2175.55	2164.40
Wheat New Indore (N)	1 Q	2187.50	2180.00
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2105.00	2112.50
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2212.50	2212.50
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	5600.00	5750.00
Yellow Peas-Kanpur (N)	1 Q	5850.00	6025.00
Zinc Mumbai (M)	1 K	171.90	172.10

* as on Feb 13, 20

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

DAY SESSION
दिवस सत्र (शुक्रवार)
कृषि जिंस

Name Exchange (Units) / Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Feb 28	19060, 19080, 18970, 19010	2190	321	26293
Mar 31	19300, 19350, 19250, 19300	1110	181	10123
Apr 30	19570, 19620, 19540, 19580	421	47	1994
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Feb 20	1772, 1805, 1772, 1790	8830	461	16350
Mar 20	1795, 1829, 1792, 1809	39140	2705	82510
Apr 20	1825, 1852, 1821, 1833	2990	278	19970
May 20	1855, 1875, 1850, 1862	190	16	6230
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1050, 1054.5, 1048.5, 1050.5	652	118	1040
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1050, 1055, 1049, 1050.5	924	497	3242
Grains				
Bajra NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	1858, 1858, 1858, 1858	20	1	120
Barley Jaipur NCDEX(1 Q)				
Apr 20	1700, 1700, 1685, 1695	40	4	2500
May 20	1695.5, 1696, 1691, 1691	90	8	2530
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	3794, 3840, 3792, 3826	4415	462	3515
Mar 20	3842, 3878, 3824, 3864	25540	3021	72690
Apr 20	3872, 3910, 3868, 3902	1340	135	7170
Maize IndusNizamabad NCDEX(1 Q)				
May 20	1715, 1715, 1715, 1715	60	1	60
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	3890, 3932, 3854, 3926	1865	186	3820
Mar 20	3920, 3970, 3882, 3962	9810	814	22685
Apr 20	3912, 3994, 3912, 3984	1690	234	6795
May 20	3948, 4000, 3948, 3978	85	17	160
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Feb 28	723.9, 729.2, 719.1, 726.5	12880	1061	42760
Mar 31	718.6, 721.9, 712.2, 720.3	12060	853	32900
Apr 30	714.6, 719.5, 709.3, 719.3	910	88	10240
Mentha Oil MCX(1 K)				
Feb 28	1150.6, 1155, 1137.2, 1139.2	194.4	431	201.6
Mar 31	1149, 1153.9, 1138.1, 1140.2	83.52	147	111.96
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Feb 20	4017, 4042, 3971, 3983	1530	82	1740
Apr 20	4047, 4052, 4024, 4045	14220	1131	17800
May 20	4070, 4078, 4049, 4073	840	74	3890
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Feb 20	838, 843.4, 836.4, 843	3925	242	13070
Mar 20	826, 829.6, 821, 827.6	15100	1964	53745
Apr 20	821, 825.6, 817, 820.8	3260	357	9415
May 20	818.4, 818.4, 818.4, 818.4	5	1	110
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Feb 20	3960, 4050, 3954, 4044	23380	2216	3785
Mar 20	3904, 3948, 3886, 3940	41015	4884	143315
Apr 20	3892, 3928, 3872, 3914	21245	2404	105295
May 20	3904, 3938, 3892, 3922	4050	525	22945
Jun 19	3942, 3942, 3942, 3942	10	2	430
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	6620, 6690, 6610, 6673	1685	200	700
Mar 20	6688, 6773, 6670, 6744	9805	1441	55290
Apr 20	6778, 6857, 6760, 6832	1730	219	6830
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Mar 20	4019, 4060, 3995, 4042	16610	1297	21230
Apr 20	3997, 4035, 3981, 4022	6080	544	19670
May 20	4030, 4060, 4024, 4048	700	63	4430
Jun 19	-, 4090, -, 4090	20	2	1100
Jul 20	-, 4136, -, 4136	10	1	10
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Mar 13	3365, 3365, 3256.2, 3273.4	3	26	7.3
Apr 15	3340, 3340, 3300, 3320	0.2	2	2
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Apr 20	6244, 6275, 6191, 6259	3700	327	7090
May 20	6268, 6282, 6237, 6264	270	27	940
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Mar 20	13560, 14025, 13540, 13990	2298	674	1902
Apr 20	13490, 13790, 13470, 13760	876	272	1908
May 20	13610, 13760, 13610, 13760	9	3	96
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Mar 20	5860, 5882, 5810, 5850	570	97	4400
Apr 20	5822, 5880, 5822, 5854	330	64	4710
धातु				
Metal- non ferrous				
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Feb 28	139.15, 139.15, 138.05, 138.15	5134	3318	5155
Mar 31	139, 139.1, 138.35, 138.4	201	153	748
Copper MCX(1 K)				
Feb 28	435, 435.6, 433.6, 433.9	13502.5	4534	12717.5
Mar 31	437.6, 438.6, 436.45, 436.8	547.5	190	1740
Lead Mini MCX(1 K)				
Feb 28	147, 147.55, 145.95, 146.2	6639	4554	5369
Mar 31	148, 148.3, 146.95, 147.2	267	208	1078
Nickel MCX(1 K)				
Feb 28	957.9, 957.9, 954.1, 955.9	7281	4422	3099
Mar 31	955.2, 955.8, 952.5, 955.1	114	75	472.5
Zinc Mini MCX(1 K)				
Feb 28	169.25, 169.85, 167.15, 167.6	28994	15800	22053
Mar 31	170.9, 171.25, 168.8, 169.25	2403	1200	6610
Apr 30	170, 170, 170, 170	1	1	13
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Apr 03	40601, 40721, 40573, 40681	3.4	2889	16.78
Jun 05	40766, 40878, 40766, 40854	0.19	137	6.28
Gold Guinea MCX(8 G)				
Feb 28	32315, 32380, 32307, 32365	0	97	0.01
Mar 31	32350, 32373, 32344, 32350	0	16	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Mar 05	40489, 40648, 40489, 40615	0.43	3755	0.87
Apr 03	40580, 40690, 40551, 40655	0.08	681	0.35
May 05	40700, 40762, 40700, 40717	0	12	0.02

Name Exchange (Units) / Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Feb 28	4010, 4018, 4007, 4016	0	481	0.01
Mar 31	4020, 4031, 4013, 4029	0	166	0
Apr 30	4030, 4030, 4030, 4030	0	1	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	45819, 46025, 45740, 45947	215.28	5769	268.29
May 05	46345, 46549, 46345, 46473	4.95	164	48.63
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	45840, 46035, 45777, 45976	22.48	15932	28.03
Apr 30	46215, 46573, 46215, 46512	2.23	1638	7.51
Jun 30	46885, 47000, 46885, 46951	0.01	10	0.2
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	45712, 46030, 45712, 45969	57.98	9459	49.96
Apr 30	46364, 46570, 46337, 46509	2.26	432	9.48
तेल एवं गैस				
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Feb 25	131.3, 131.3, 128.6, 129.5	65025mb	26855	52335mb
Mar 26	133.6, 133.6, 132, 132.6	2406mb	1375	7266mb
Apr 27	137.5, 138.1, 136.9, 137.3	144mb	98	926mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Feb 19	3685, 3735, 3667, 3726	16415bl	91542	3068bl
Mar 19	3712, 3763, 3697, 3754	678bl	4503	466bl
Apr 20	3723, 3795, 3723, 3777	2bl	22	7bl

सायं सत्र (गुरुवार)
कृषि जिंस

Name Exchange (Units) / Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Feb 28	19190, 19210, 19010, 19100	3618	529	26471
Mar 31	19440, 19460, 19300, 19360	1297	187	9779
Apr 30	19700, 19730, 19600, 19610	548	79	1769
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1061, 1064, 1051, 1052.5	840	150	1012
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1062.5, 1065, 1050, 1053.5	1389	771	3398
Oil and Oilseeds				
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Feb 28	732.3, 743.1, 717.6, 723.6	29910	2335	41920
Mar 31	725, 735.3, 711.1, 717.3	18830	1377	31980
Apr 30	723, 731.5, 707, 714	2810	249	9790
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Feb 20	846.6, 852.2, 837.8, 841.4	4800	461	14820
Mar 20	833.2, 842, 821.8, 826.8	28355	3068	53770
Apr 20	825.4, 835, 817.6, 822.4	4990	616	9295
धातु				
Metal- non ferrous				
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Feb 28	138.1, 139.5, 137.65, 139.2	12828	8376	4755
Mar 31	138.45, 139.6, 138.2, 139.3	639	480	798
Copper MCX(1 K)				
Feb 28	434.6, 436, 432.2, 435.6	33470	11243	10502.5
Mar 31	437.35, 438.75, 435, 437.95	955	367	1502.5
Lead Mini MCX(1 K)				
Feb 28	145.6, 147.8, 145.35, 147.45	16685	10589	4786
Mar 31	146.65, 148.5, 146.35, 148.2	486	417	1009
Nickel MCX(1 K)				
Feb 28	951.2, 962.6, 948.9, 961.3	29937	17891	1975.5
Mar 31	953, 960.3, 950.6, 959.4	640.5	406	468
Zinc MCX(1 K)				
May 29	173, 174.5, 171.95, 173.15	3	3	15
Zinc Mini MCX(1 K)				
Feb 28	168.3, 170.7, 167.7, 169.7	56927	32169	18409
Mar 31	169.6, 171.9, 169.15, 171.2	2448	1607	6227
Apr 30	171, 171.5, 171, 171.25	2	2	13
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Apr 03	40551, 40700, 40513, 40656	9.87	8539	16.2
Jun 05	40748, 40872, 40680, 40830	0.32	256	6.16
Gold Guinea MCX(8 G)				
Feb 28	32349, 32414, 32316, 32363	0.01	410	0.01
Mar 31	32364, 32389, 32316, 32365	0	121	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Mar 05	40474, 40625, 40460, 40580	1.49	12861	0.77
Apr 03	40551, 40675, 40510, 40628	0.25	2137	0.33
May 05	40631, 40735, 40578, 40703	0.01	70	0.02
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Feb 28	4013, 4020, 4009, 4014	0	1412	0.01
Mar 31	4021, 4032, 4021, 4025	0	481	0
Apr 30	4032, 4040, 4023, 4035	0	8	0
May 29	3921, 4121, 3921, 4021	0	4	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	45590, 45995, 45590, 45799	574.62	15906	249.87
May 05	46260, 46523, 46237, 46343	25.98	600	47.13
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	45683, 46018, 45681, 45828	67.5	48066	25.95
Apr 30	46216, 46548, 46200, 46389	7.06	5107	7.42
Jun 30	46996, 47000, 46798, 46914	0.03	24	0.2
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	45630, 46000, 45630, 45821	184.88	29478	41.86
Apr 30	46288, 46541, 46250, 46386	8.09	1506	9.29
तेल एवं गैस				
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Feb 25	131.6, 133.5, 130.7, 132	176008mb	75300	43200mb
Mar 26	134.1, 136.1, 133.4, 134.6	6583mb	4050	6634mb
Apr 27	139.4, 140.8, 138.4, 139.2	454mb	245	911mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Feb 19	3675, 3703, 3614, 3675	47160bl	261223	1966bl
Mar 19	3695, 3730, 3643, 3702	1683bl	11698	463bl
Apr 20	3721, 3774, 3656, 3751	8bl	54	6bl

g-grams, k-kilograms, q-quintals, t-tonnes, b-bales,bl-barels,mb-mmBTU,m-Mnd; Quantity & Open interest in tonnes except for crude oil and natural gas; For Gas is '000 mmBTU & for crudeoil in '000 barrel; Market price in ₹.

बजट में बुनियादी ढांचे पर होगा जोर

उत्तर प्रदेश सरकार का इस बार 5.15 लाख करोड़ का हो सकता है बजट

बीएस संवाददाता
लखनऊ, 14 फरवरी

- बजट में गोरखपुर व आगरा मेट्रो परियोजनाओं को गति देने के लिए खासी धनराशि का आवंटन किया जा सकता है
- गोरखपुर लिंक व बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए भी धन का आवंटन किया जा सकता है
- आवास एवं नगर विकास विभाग ने इस बार के बजट में 3,400 करोड़ रुपये की मांग की
- बजट में आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 246 करोड़ रुपये तो कानपुर मेट्रो के लिए 81 करोड़ रुपये की मांग की गई
- गोरखपुर मेट्रो परियोजना के लिए 150 करोड़ रुपये की मांग की गई

उत्तर प्रदेश सरकार का इस बार के बजट में एक्सप्रेसवे, सड़कों, शहरी सुविधाओं सहित मेट्रो परियोजनाओं को भारी धनराशि के आवंटन की उम्मीद है। प्रदेश सरकार का इस बार का बजट 5.15 लाख करोड़ रुपये तक हो सकता है जो बीते साल के बजट से 10 फीसदी से ज्यादा होगा।

वित्त विभाग के अधिकारियों की मानों तोइस बार के बजट में गोरखपुर व आगरा मेट्रो परियोजनाओं को गति देने के लिए खासी धनराशि का आवंटन किया जा सकता है जबकि गोरखपुर लिंक व बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए भी धन का आवंटन किया जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास इसी महीने की 29 तारीख को किया जाएगा। डिफेंस कारीडोर को हाल ही में राजधानी में संपन्न हुए एशिया के सबसे बड़े रक्षा मेले में निवेशकों का बढ़िया प्रतिक्रिया मिलने के बाद यहां की अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए धन का आवंटन किया जाएगा। इस कॉरिडोर के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश को 3,500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। हाल ही में राजधानी में आयोजित रक्षा मेले में डिफेंस कॉरिडोर में अपना उद्यम लगाने के 23 करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

> उत्तर प्रदेश का सालाना बजट अगले सप्ताह मंगलवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा और उसी दिन बजट प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 17 शहरों को स्मार्ट एवं सेफ सिटी के तौर पर विकसित किए जाने के एलान किया है। इनमें से 10 शहर तो केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना के अंग हैं जबकि सात शहरों को प्रदेश सरकार ने अपनी ओर से शामिल किया है। शहरों के विकास के लिए प्रदेश सरकार के आवास एवं नगर विकास विभाग ने इस बार के बजट में 3,400 करोड़ रुपये की मांग की है। जहां तक मेट्रो परियोजनाओं का सवाल है तो इस बार के बजट में आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 246 करोड़ रुपये तो कानपुर मेट्रो के लिए 81 करोड़ रुपये की मांग की गई है। गोरखपुर मेट्रो परियोजना के लिए 150 करोड़ रुपये की मांग की गई है। प्रदेश सरकार जहां कानपुर मेट्रो परियोजना पर निर्माण कार्य शुरू कर चुकी है वहीं गोरखपुर व आगरा मेट्रो परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बन चुकी है।

प्रदेश सरकार इस बार के बजट में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर बनने वाले अटल आवासीय विद्यालय के लिए भी धनराशि का आवंटन करेगी। हाल ही में प्रदेश सरकार ने स्नातक की शिक्षा प्राप्त युवाओं को 6-6 माह का प्रशिक्षण देने और इस अवधि में उन्हें 2,500 रुपये प्रति माह का छात्रवृत्ति देने का ऐलान किया है। इस योजना के लिए भी धन का आवंटन इस बार के बजट में किया जाएगा।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश का सालाना बजट अगले सप्ताह मंगलवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा। मंगलवार को ही सुबह मंषिपरिषद की बैठक में बजट प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार का बजट सत्र 13 फरवरी के शुरू हुआ है।

सावरकर ने डाली महाराष्ट्र सरकार में दरार

सुशील मिश्र
मुंबई, 14 फरवरी

- शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच एल्गार परिषद् को लेकर दरार पड़ गई
- उद्धव ठाकरे द्वारा मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपे जाने से सहयोगी दल एनसीपी नाराज

शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के बीच एल्गार परिषद् को लेकर दरार पड़ गई है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपे जाने से सहयोगी दल एनसीपी नाराज है। इस फैसले पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने नाराजगी व्यक्त की है। हालांकि मुख्यमंत्री के बाद अदालत ने भी भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की जांच एनआईए कौ सौंपने का आदेश दिया।

भीमा-कोरगांव हिंसा मामले की जांच मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट में हस्तांतरित करने का आदेश पुणे के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसआर नवांदर ने शुक्रवार को दिया। न्यायाधीश नवांदर राज्य सरकार की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें जांच को एनआईए को हस्तांतरित करने पर आपत्ति जताई गई है। अदालत के फैसले से ठीक एक दिन पहले सीएम उद्धव ठाकरे ने भी एनआईए के हाथ इसकी जांच करवाने का निर्णय ले लिया था। मुख्यमंत्री के फैसले पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था का मामला राज्य का है और राज्य सरकार को ऐसे केंद्र के निर्णय का समर्थन नहीं करना चाहिए। शरद पवार का कहना है कि भीमा कोरेगांव मामले में महाराष्ट्र सरकार कुछ एक्शन लेने वाली थी, इसलिए केंद्र ने एल्गार परिषद के मामले को अपने हाथ में ले लिया। शरद पवार से पहले एनसीपी नेता व राज्य गृह मंत्री अनिल देशमुख नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के पास शक्ति है। उन्होंने मेरे प्रस्ताव को खारिज कर दिया और जांच करने के लिए एनआईए को हरी झंडी दे दी। बड़ा नीतिगत निर्णय लेने से पहले, राज्य सरकार को केंद्रीय मंत्रालय को बताना चाहिए था कि उसके निर्णय पर पुनर्विचार करने की जरूरत है।

एल्गार परिषद् 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में शनिवार वाडा में दलित समूहों और अन्य लोगों द्वारा आयोजित एक सभा थी। इसके एक दिन बाद (एक जनवरी 2018) भीमा कोरेगांव युद्ध के वार्षिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गांववाले पहुंचे थे, जहां हिंसा भड़क गई थी। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि अन्य घायल हुए थे। तत्कालीन भाजपा-शिवसेना सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। वहीं नक्सलियों से सहानुभूति रखने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने एल्गार परिषद् का समर्थन किया था। एनसीपी, कांग्रेस और कुछ दलित समूहो ने हिंसा के लिए हिंदुत्व संगठनों को जिम्मेदार ठहराया था। गौरतलब है कि शुक्रवार सुबह महाराष्ट्र सरकार की पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक थी जिसमें दोपहर तीन बजे यह मामला एनआईए को हस्तांतरित करने का आदेश दिया गया है। इस मामले पर शरद पवार का कहना है कि यह संविधान के अनुसार गलत है क्योंकि अपराध की जांच राज्य का अधिकार क्षेत्र है।

वीर सावरकर को लेकर भी सत्ता में शामिल दलों के बीच दरार पड़ती जा रही है। शिवसेना सावरकर को आदर्श मानती है जबकि कांग्रेस एनसीपी सावरकर को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। हिंदुत्व की विचारधारा और स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के बारे में आलोचात्मक लेख प्रकाशित करने वाली कांग्रेस की पत्रिका 'शिदोरी' पर प्रतिबंध लगाने की फडणवीस की मांग के बारे में एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है। यह दिखाता है कि वर्तमान सरकार में लोग अपने विचार खुलकर व्यक्त कर सकते हैं और उनके विचारों को दबाया नहीं जा रहा। भाजपा ने 'द्वेषपूर्ण' सामग्री छापने पर पत्रिका पर प्रतिबंध और पार्टी से माफी की मांग की। फडणवीस ने शिवसेना को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि सावरकर पर कांग्रेस के हमलों को वह अनदेखा कर रही है। उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे नीत दल को यह बताना चाहिए कि अपने सत्तारूढ़ साझेदार के हाथों वह और कितना अपमान बर्दाश्त कर सकता है। गौरतलब है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर प्रदेश में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार बनाई है।

वस्त्र -खाद्य प्रसंस्करण में मोटा निवेश

बीएस संवाददाता
भोपाल, 14 फरवरी

मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा आज राजधानी नई दिल्ली में आयोजित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रदेश में टेक्सटाइल और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को लेकर कई बड़ी घोषणाएं हुईं। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ ने भी इन क्षेत्रों के लिए विशेष रियायतों की घोषणा भी की।

कपड़ा उद्योग के शीर्ष उद्योगपतियों ने इस अवसर पर प्रदेश में 3,250 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की। इससे करीब 14,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। कपड़ा उद्योग की शीर्ष कंपनियों में से एक ट्राइडेंट समूह के चेयरमैन राजेंद्र गुप्ता ने राजधानी भोपाल में 3,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं गोकलदास एक्सपोर्ट के प्रबंध निदेशक शिवा गणपति ने भोपाल में 50 करोड़ रुपये के निवेश और 3,000 लोगों को रोजगार देने की बात कही। मयूर यूनिकोटर्स के महाप्रबंधक स्वप्निल व्यास ने ग्वालियर में 150 करोड़ रुपये के निवेश और 1,000 लोगों के रोजगार की घोषणा की।